PERFECT 7
FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

मई 2022 / Issue -2

यूपीएससी और राज्य आधारित पीसीएस परीक्षाओं के लिए उपयोगी

- भारत में रोजगार परिदृश्य
- जर्मनी-भारत अंतर सरकारी परामर्श
- भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग- चुनौतियां और अवसर
- भारत में वनाग्नि और वनवासी समुदाय
- भारत में पेट्रोलियम तेल के दाम में हो रही वृद्धि और मुद्रास्फीति
- वैश्विक राजनीति के केंद्र में भारत
- न्यायपालिका तथा कार्यपालिका में टकराव

dhyeyaias.com

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

IAS
TARGET 2023-24

PMI
(PRE+MAINS+INTERVIEW)
Programme-2022-23

Starting From
19th June 2022
12:00 Noon

उद्देश्य :

- यूपीएससी की परीक्षा के हर चरण में सभी छात्रों की तैयारी तथा सहायता।
- यूपीएससी परीक्षा की बदलती प्रवृत्ति के साथ हमारे छात्रों के लिए एक अद्यतन प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान करना।
- वन टू वन डिस्कशन के माध्यम से यूपीएससी परीक्षा में छात्रों द्वारा की जाने वाली सामान्य गलतियों को समाप्त करना।
- राष्ट्र निर्माण की ओर ले जाने वाले यूपीएससी उम्मीदवारों के क्षमता निर्माण की पूरी प्रक्रिया निर्मित करना।

मुख्य विशेषताएँ :

- संक्षिप्त, सारगर्भित और यूपीएससी परीक्षा की प्रवृत्ति के अनुसार पाठ्यक्रम।
- विषयवार तैयारी।
- समर्पित विशेषज्ञों की टीम द्वारा प्रश्नों की बदलती प्रवृत्तियों का अनुसंधान और विश्लेषण।
- प्रीलिम्स, मेन्स और पर्सनैलिटी टेस्ट पर विशेष ध्यान।
- भारत सरकार के विशिष्ट / महत्वपूर्ण प्रकाशनों के साथ 1 वर्ष के भीतर यूपीएससी, परीक्षा के पाठ्यक्रम का व्यापक कवरेज।
- प्रथम चरण (जनवरी से जून-06 महीने) - यूपीएससी, और अन्य परीक्षाओं को लक्षित करने के लिए करेंट अफेयर्स के साथ कक्षा 6 से 10वीं की एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित फाउंडेशनल सिलेबस कवरेज।
- दूसरा चरण (जुलाई से दिसंबर-06 महीने) - करेंट अफेयर्स के साथ 11वीं और 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित एडवांस सिलेबस कवरेज।
- प्रत्येक पीएमआई परीक्षा के साथ व्यक्तित्व मूल्यांकन और फीडबैक।

Fee : (Including GST)

☞ For Dhyeya Students : Rs. 2,000/-
☞ For Other Students : Rs. 5,000/-

This Fee is valid for 12 Months consisting 12 Tests

Call: 9205274741 / 42

www.dhyeyaias.com

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Director's Message

Mr. Vinay Kumar Singh

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।
सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

Yours very truly,

Vinay Kumar Singh
CEO and Founder

Mr Q H Khan

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहां छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Yours very truly,

Q H Khan
Managing Director

प्रस्तावना

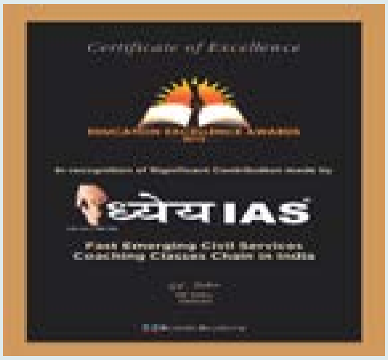

समसामयिक मुद्दे अथवा करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट 7 मैगजीन को विद्यार्थी जगत के समक्ष माह में दो बार रखा जा रहा है. आईएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के तथ्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाय. परफेक्ट 7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कंटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है. इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है. एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, पेपर 4 के लिए एथिक्स की केस स्टडीज को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्वों के जीवन और भूमिकाओं, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर एक माह के 14 सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें सर्वाधिक जोर पर्यावरण पारिस्थितिकी, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी , अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर है. शब्दावली और अन्य आयामों एक छोटा खंड भी परफेक्ट 7 मैगजीन का पार्ट होगा.

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ाने के लिए ब्रेन बूस्टर्स को 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैश्विक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहेगी. इस मैगजीन को केवल तथ्यों या केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नही बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का विजन यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें. हमें उम्मीद हैं कि परफेक्ट 7 अपने नए रूप में आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा और इसके साथ ही आप सभी के सुझावों का स्वागत रहेगा.

विनय कुमार सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7 TEAM

संपादक	• विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	• क्यू. एच. खान
सहसंपादक	• गौतम तिवारी
उप-संपादक	• आशुतोष मिश्र
	• सौरभ चक्रवर्ती
सहायक उप-संपादक	• अमन कुमार
प्रकाशन प्रबंधक	• डॉ.एस.एम.खालिद
संपादकीय सहयोग	• प्रिंस, गौरव चौधरी, देवेंद्र सिंह, लोकेश शुक्ल
मुख्य लेखक	• विवेक ओझा
सहायक लेखक	• मृत्युंजय त्रिपाठी,
मुख्य समीक्षक	• ए.के श्रीवास्तव
	• विनीत अनुराग
	• बाघेन्द्र सिंह
आवरण सज्जा एवं विकास	• प्रगति केसरवानी
	• पुनीष जैन
टंकण	• सचिन
	• तरून
कार्यालय सहायक	• राजू, चन्दन, अरुण

साभार : PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक जागरण, डाउन टू अर्थ, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीक्ली, योजना, कुरुक्षेत्र, द प्रिंट

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.
AN ISO 9001:2008 COMPANY

Face to Face Centres

MUKHERJEE NAGAR	: 9205274741, 9205274742
RAJENDRA NAGAR	: 9205274743
LAXMI NAGAR	: 9205212500, 9205962002
ALLAHABAD	: 0532-2260189, 8853467068
LUCKNOW (ALIGANJ)	: 0522-4025825, 9506256789
LUCKNOW (GOMTINAGAR)	: 7234000501, 7234000502
GREATER NOIDA	: 9205336037, 9205336038
KANPUR	: 7887003962, 7897003962
BHUBANESWAR	: 8599071555
SRINAGAR (J&K)	: 9205962002

PERFECT 7
FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

विषय सूची

समसामयिक लेख ———————— 1-14

- भारत में रोजगार परिदृश्य
- जर्मनी-भारत अंतर सरकारी परामर्श
- भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग- चुनौतियां और अवसर
- भारत में वनाग्नि और वनवासी समुदाय
- भारत में पेट्रोलियम तेल के दाम में हो रही वृद्धि और मुद्रास्फीति
- वैश्विक राजनीति के केंद्र में भारत
- न्यायपालिका तथा कार्यपालिका में टकराव

संक्षिप्त मुद्दे राष्ट्रीय -------------------- 15-16

संक्षिप्त मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय -------------------- 17-18

संक्षिप्त मुद्दे पर्यावरण -------------------- 19-20

संक्षिप्त मुद्दे विज्ञान एवं तकनीक -------------------- 21-22

संक्षिप्त मुद्दे आर्थिक -------------------- 23-24

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें --------- 25-28

समसामयिक घटनाएं एक नजर में -------------------- 29

ब्रेन बूस्टर -------------------- 30-36

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा समसामयिक बहुविकल्पीय प्रश्न -------------------- 37-42

GS Paper IV के लिए हल केस स्टडी -------------------- 43

व्यक्ति विशेष -------------------- 44

इतिहास विषय की शब्दावलियां -------------------- 45

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES®
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

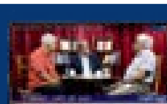

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

भारत में रोजगार परिदृश्य

चर्चा में क्यों ?

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, 2021-22 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में शहरी भारत में बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर तिमाही के 9.8 प्रतिशत से गिरकर 8.7 प्रतिशत हो गई। 2020-21 की समान तिमाही में यह 10.3 प्रतिशत थी।
- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) की एक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2022 में, भारत की श्रम भागीदारी दर (LPR) फरवरी के 39.9 प्रतिशत से गिरकर 39.5 प्रतिशत हो गई।

उपरोक्त दो हालिया रिपोर्टें भारत में एक दिलचस्प रोजगार परिदृश्य दिखा रही हैं, जहां एक तरफ महामारी के झटके के बाद रोजगार के अवसरों में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, दूस. री ओर, कम लोग काम की तलाश कर रहे हैं।

रोजगार- मूल अवधारणा

रोजगार का तात्पर्य नौकरी होने की स्थिति से है। भारत में रोजगार से संबंधित निम्नलिखित प्रमुख संकेतक हैं।

- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) - स्थ्व्द को जनसंख्या में श्रम बल (अर्थात काम करने वाले या तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब्ध) में व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) - WPR को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- बेरोजगारी दर (UR) - UR को श्रम बल में व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

भारत में रोजगार से संबंधित मुद्दे

- रोजगार के अवसरों में धीमी गति से सुधार के बावजूद, भारत की बेरोजगारी दर अभी भी उच्च है। इस स्थिति के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारत में अभी भी कौशल बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है जिसके कारण उद्योग की वर्तमान और तेजी से बदलती आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त कर्मचारियों की कमी है। कपड़ा, खिलौने और जूते-चप्पल निर्माण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में धीमी वृद्धि भी उच्च बेरोजगारी में योगदान करती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार प्रदान करने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं लेकिन वे अभी भी भारत में प्रारंभिक अवस्था में हैं। भारत का विकास प्रक्षेपवक्र भी असमान रहा है क्योंकि भारत पर्याप्त विनिर्माण विकास के बिना ही कृषि से सीधे सेवाओं में कूद गया, जो रोजगार सृजन के लिए अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
- भारत में दृश्य और अदृश्य दोनों ही तरह की अल्परोजगारी का मुद्दा भी है। दृश्य अल्परोजगारी उस स्थिति को संदर्भित करती है जब कोई व्यक्ति सप्ताह में 40 घंटे से कम काम करता है। उदाहरण के लिए, एक ड्राइवर जो कम मांग के कारण सप्ताह में केवल 20 घंटे कार चलाता है। यदि एक योग्य व्यक्ति कम कौशल की आवश्यकता वाली नौकरी का विकल्प चुन रहा है, तो इस स्थिति को अदृश्य अल्परोजगारी के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, एक इंजीनियरिंग स्नातक जो एक क्लर्क के रूप में काम कर रहा है। बेरोजगारी की इस समस्या का अंदाजा हमारे कृषि से जुड़े जीडीपी के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। भारत में, कृषि सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20% का योगदान करती है, लेकिन 40% से अधिक श्रम शक्ति इसमें शामिल है, इस प्रकार यह बड़ी संख्या में अल्परोजगारी की उपस्थिति का संकेत है। अल्परोजगार की यह स्थिति मुख्य रूप से कौशल-नौकरी बेमेल होने के कारण है। अधिकांश नौकरी की उपलब्धता ब्लू-कालर क्षेत्रों में है, जबकि भारत में विश्वविद्यालय की डिग्री रखने वाले उच्च शिक्षित युवाओं का अनुपात बढ़ रहा है। इसके अलावा, तेजी से तकनीकी परिवर्तन भी एक विशेष क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अन्य क्षेत्रों में अल्परोजग. ार की स्थिति पैदा करती हैं, यदि कोई नई तकनीक उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में आती है। नीति आयोग के तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा 2017-18 से 2019-20 तक के अनुसार भारत में बेरोजगारी की तुलना में अल्परोजगारी की समस्या बहुत अधिक है।
- भारत में श्रम शक्ति की भागीदारी बहुत कम है। इसके अलावा, भारत में शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम महिला श्रम शक्ति भागीदारी अनुपात है, जो बांग्लादेश की तुलना में बहुत कम है और सऊदी अरब से भी कम है। कुल मिलाकर कम श्रम भागीदारी दर को विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा डिस्करेज्ड ड्राप आउट की घटना द्वारा समझाया गया है। उनके विचारों के अनुसार, जब लोगों को वांछित स्थिति की नौकरी नहीं मिलती है या वे समझते हैं कि नौकरी का बाजार अनुकूल नहीं है, तो वे श्रम बाजार से हट जाते हैं। कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी करने और अपनी डिग्री प्राप्त करने के कारण, श्रम बाजार से जानबूझकर बाहर रहने के रुझान के द्वारा कम श्रम भागीदारी की व्याख्या की है। श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी को उपरोक्त कारकों के साथ-साथ महिलाओं के खिलाफ दिन-प्रतिदिन भेदभाव और सुरक्षा, कार्यस्थल के घर से दूर होने, परिवहन आदि जैसे मुद्दों के संयोजन द्वारा समझाया गया है।

- भारतीय श्रम बाजार में नौकरियों का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक हैं। औपचारिक नौकरियां देश में कुल रोजगार के 15% से कम हैं, जबकि 85% से अधिक अनौपचारिक नौकरियां हैं। इसमें न केवल कृषि बल्कि खुदरा जैसे बड़े क्षेत्र भी शामिल हैं। अनौपचारिक श्रमिक आमतौर पर छोटे घरेलू व्यवसायों के मालिक होते हैं, कोई सड़क के किनारे चाय बना रहा होता है, फल विक्रेता या सुरक्षा गार्ड होता है। अनौपचारिक नौकरियां श्रमिकों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती हैं और इस प्रकार उनके भाग्य को अनिश्चित बना देती हैं। औपचारिक नौकरियों की कमी के इस संकट के लिए मुख्य रूप से एक पिछ. ड़े विनिर्माण क्षेत्र को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो विभिन्न सरकारी प्रयासों के बावजूद अभी तक उठा नहीं है। यहां तक कि 1991 के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सुधारों से भी औपचारिक क्षेत्र में नौकरियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ रहे हैं।
- तेजी से बदलती तकनीक के साथ-साथ COVID महामारी ने भी रोजगार की प्रकृति को प्रभावित किया है। तकनीकी परिवर्तनों ने गिग इकॉनमी को बढ़ावा दिया है, जहां श्रमिकों को बहुत तेज गति से काम पर रखा जा सकता है और निकाल दिया जा सकता है। तकनीकी रूप से शिक्षित श्रमिकों की भी मांग बढ़ रही है। COVID महामारी के कारण, घर से काम करना एक नयी सामान्य स्थिति हो गई है। इसने कई क्षेत्रों जैसे ई-कॉमर्स, डिलीवरी सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा आदि में नौकरी की वृद्धि की है।

रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी उपाय

सरकार ने रोजगार से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। स्किल इंडिया मिशन कौशल प्रशिक्षण के साथ औद्योगिक आवश्यकताओं को मैप करने की कोशिश करता है, इस प्रकार 3 डी प्रिंटिंग, डेटा साइंस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग आदि जैसे उच्च तकनीकी क्षेत्रों में नौकरियों को बढ़ावा देता है। विनिर्माण क्षेत्र में धीमी वृद्धि, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, मेक इन इंडिया के माध्यम से तेजी से दूर की जा रही है, जिसका उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना और 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना है। सरकार स्टार्टअप इंडिया के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वरोजगार सृजन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार कोष आदि जैसे कदमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। बेरोजगारों को एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को भी चला रही है।

आगे का रास्ता

उपरोक्त उपायों को ठीक से लागू किए जाने पर अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। बेरोजगारी से निपटने के संबंध में एक उपयुक्त दीर्घकालिक दृष्टि की भी आवश्यकता है, जो रोजगार सृजन में आपूर्ति और मांग-पक्ष दोनों से संबंधित समस्याओं का समाधान करती हो। इस दृष्टिकोण को मजबूत और वस्तुनिष्ठ आंकड़ों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग नीति निर्माताओं द्वारा किया जा सके। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, विकलांगों आदि जैसे कमजोर वर्गों के लिए रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तभी हम 'सबका साथ सबका विकास' के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

NOTES

जर्मनी-भारत अंतर सरकारी परामर्श

चर्चा में क्यों?

- भारत और जर्मनी ने व्यापार, ऊर्जा, सांस्कृतिक संबंधों के विस्तार पर चर्चा की और नौ समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए।

प्रसंग:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने हरित और सतत विकास के लिए एक भारत-जर्मन साझेदारी शुरू करने का निर्णय लिया है जिसके तहत जर्मनी ने भारत की हरित विकास योजनाओं का समर्थन करने के लिए 2030 तक €10 बिलियन की अतिरिक्त विकास सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
- ग्लासगो की सीओपी बैठक में, भारत ने अपनी जलवायु दायित्व को बढ़ाया और दुनिया को दिखाया कि हमारे लिए हरित और सतत विकास आस्था का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर स्कोल्ज को (विकास सहायता के लिए) धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया, हमने एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है जो दोनों देशों में हरित हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद करेगी।

अंतर सरकारी परामर्श क्या है?

- अंतर-सरकारी परामर्श व्यापक क्षेत्रों में भारत और जर्मनी के बीच सहयोग की समीक्षा करते हैं और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने का भी लक्ष्य रखते हैं।
- आईजीसी में पारस्परिक हित के क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
- अंतर-सरकारी परामर्श दोनों देशों के बीच दोस्ती की विशेष प्रकृति को दर्शाता है।

अंतर-सरकारी परामर्श के प्रमुख क्षेत्र:

- आईजीसी एक अनूठा तंत्र है जो कई क्षेत्रों में सहयोग और साझेदारी पर द्विपक्षीय चर्चा में शामिल होने के लिए दोनों नेताओं सहित दोनों पक्षों के कई मंत्रियों और अधिकारियों को एक साथ लाता है। आईजीसी के फोकस क्षेत्रों में वैश्विक सुरक्षा नीति के मुद्दे और जलवायु संकट से निपटने के सामान्य प्रयास शामिल हैं।
- दोनों पक्षों ने IGC के दौरान कुल नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनमें मुख्यत: शामिल हैं।
- अक्षय ऊर्जा साझेदारी।
- प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी।
- तीसरे देशों में त्रिकोणीय विकास सहयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर संयुक्त पहल।
- वन परिदृश्य बहाली पर संयुक्त पहल।

छठा अंतर-सरकारी परामर्श- प्रमुख निर्णय:

हरित और सतत ऊर्जा भागीदारी

- भारत और जर्मनी इंडो-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के इनपुट के आधार पर हरित और सतत विकास के लिए एक हाइड्रोजन रोडमैप विकसित करने पर सहमत हुए, जिसे इंडो-जर्मन एनर्जी फोरम द्वारा समर्थित किया जाएगा।
- दोनों नेताओं ने एक बयान में नवीन सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक हरित और टिकाऊ ऊर्जा साझेदारी स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।
- साझेदारी एसडीजी और जलवायु कार्रवाई पर भारत-जर्मनी सहयोग के लिए एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना करती है और इसमें बिजली ग्रिड, भंडारण और बाजार डिजाइन के लिए संबंधित चुनौतियों को शामिल किया जाएगा ताकि उचित ऊर्जा संक्रमण को सक्षम किया जा सके।
- जर्मनी ने साझेदारी के तहत तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करने की अपनी मंशा व्यक्त की, जिसमें 2020-2025 तक 1 बिलियन यूरो तक का रियायती ऋण शामिल है।
- जर्मनी 2030 तक 10 बिलियन यूरो की नई और अतिरिक्त विकास सहायता की अग्रिम प्रतिबद्धता बनाने पर भी सहमत हुआ है।

कृषि पारिस्थितिकी सहयोग

- भारत और जर्मनी कृषि क्षेत्र में 'कृषि पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन' पर सहयोग स्थापित करने पर भी सहमत हुए। खाद्य सुरक्षा, आय, जलवायु लचीलापन, जैव विविधता, बेहतर मिट्टी, पानी की उपलब्धता और वन बहाली पर ध्यान केंद्रित करके सहयोग से भारत की ग्रामीण आबादी और छोटे पैमाने के किसानों को लाभ होने की उम्मीद है।
- जर्मनी ने परियोजना की तैयारी और धन की उपलब्धता के आधार पर कृषि-पारि. स्थितिकी सहयोग के लिए 2025 तक 300 मिलियन यूरो तक वित्तीय और तकनीकी सहयोग और रियायती ऋण प्रदान करने का इरादा व्यक्त किया।
- दोनों देश गरीबी से लड़ने, जैव विविधता को संरक्षित करने और बहाल करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए बॉन चैलेंज के तहत वन परिदृश्य को बहाल करने में सहयोग को गहरा करने पर भी सहमत हुए।

तीसरे देशों में त्रिकोणीय विकास सहयोग परियोजनाएं

- दोनों देशों ने विकास सहयोग में व्यक्तिगत अनुभवों और ताकत के आधार पर 'त्रिकोणीय विकास सहयोग' पर काम करने का फैसला किया और संयुक्त राष्ट्र एसडीजी की उपलब्धि का समर्थन करने के लिए तीसरे देशों में समावेशी, टिकाऊ और व्यवहार्य परियोजनाओं की पेशकश की।
- दोनों देशों ने ग्रह की सुरक्षा और समावेशी और सतत विकास को सक्षम करने के लिए अपनी संयुक्त जिम्मेदारी को भी स्वीकार किया।

यूक्रेन संकट पर भारत और जर्मनी

(पीएम ने कहा कि भारत रूस-यूक्रेन संघर्ष के मानवीय प्रभाव को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि संघर्ष की शुरुआत से ही भारत ने हिंसा को रोकने का आह्वान किया था और संकट को सुलझाने के लिए बातचीत के महत्व पर जोर दिया था। "कोई विजेता नहीं होगा। सब भुगतेंगे। इसलिए हम शांति के पक्षधर हैं।"

(मोदी ने बताया कि संकट के कारण उत्पन्न व्यवधान के कारण, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया में भोजन और उर्वरक की कमी है और विकासशील देश और गरीब देश सबसे अधिक पीड़ित है।

(दोनों देशों ने शत्रुता को तत्काल सम. प्त करने की आवश्यकता को भी दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि समकालीन वैश्विक व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर बनाई गई है।

(उन्होंने यूक्रेन संघर्ष के अस्थिर प्रभाव और इसके व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावों पर भी चर्चा की और इस मुद्दे पर निकटता से जुड़े रहने पर सहमत हुए।

ग्रीन मोबिलिटी में भारत-जर्मन अनुसंधान सहयोग

अनुसंधान सहयोग के क्षेत्र में भी, ग्रीन मोबिलिटी और शहरी परिवहन के लिए स्मार्ट

समाधानों की खोज के क्षेत्र में विकास हो रहे हैं। 2018 में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) - खड़गपुर ने इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर एक शोध केंद्र स्थापित करने के लिए म्यूनिख के तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ सहयोग शुरू किया। अनुसंधान केंद्र वर्तमान में IIT&खड़गपुर में स्थित है, लेकिन म्यूनिख में भी एक कार्यालय स्थापित किया जाना है। केंद्र मुख्य रूप से शहरी गतिशीलता से संबंधित तीन पहलुओं पर केंद्रित है। ये हैं :

- एकीकृत एंड-टू-एंड परिवहन प्रणाली।
- भारत विशिष्ट ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियां।
- ऑटोमोटिव सिस्टम और सॉफ्टवेयर का सहयोगात्मक विकास।

यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौता वार्ता:

(भारत और जर्मनी ने भी द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की विशाल संभावनाओं को रेखांकित किया और एक मुक्त व्यापार समझौते में यूरोपीय संघ और भारत के बीच आगामी वार्ता के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया।

(भारत और जर्मनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला, विविध, जिम्मेदार और टिकाऊ बनाने पर सहमत हुए।

(मोदी ने आशा व्यक्त की कि भारत-यूरोपीय संघ की एफटीए वार्ता संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित एफटीए सौदों की तर्ज पर तेजी से आगे बढ़ेगी जो रिकॉर्ड समय में पूरे हुए थे।

उन्होंने कहा कि भारत के कुशल श्रमिकों और पेशेवरों ने कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभान्वित किया है और भारत-जर्मन व्यापक गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी पर काम किया जा रहा है, जिससे कार्यबल की सुचारू आवाजाही हो सकेगी।

NOTES

भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग- चुनौतियां और अवसर

चर्चा में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजाइन और नवाचार में भारत को वैश्विक नेता बनाने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति का गठन किया है। विशेष. ज्ञों की सलाहकार समिति में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, स्थापित शिक्षाविद के साथ उद्योग और डोमेन विशेषज्ञ भी शामिल हैं।

भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग

भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग अभी प्रारंभिक अवस्था में है। हालांकि भारत के पास चिप डिजाइन में महत्वपूर्ण विशेषज्ञता और प्रतिभा है, लेकिन इसकी निर्माण क्षमता को आगे बढ़ाना बाकी है। हाल ही में भारत सरकार अपनी कई पहलों के माध्यम से सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है। भारत सरकार ने हमारे देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए 76000 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह प्रोग्राम सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता के साथ एक स्वतंत्र इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन स्थापित किया गया है। यह मिशन सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में भारत की दीर्घकालिक रणनीति तैयार करेगा। सरकार ने स्कीम फार द प्रमोशन आफ मैनुफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स (SPECS) भी शुरू की है। इन प्रयासों ने प्रतिक्रिया दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार को सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाइयां स्थापित करने के लिए कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं।

चुनौतियाँ

उपरोक्त प्रयासों के बावजूद, अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं।

- निर्माण इकाई स्थापित करने में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है। निवेश और पेबैक के बीच एक लंबी प्रक्रिया अवधि भी होती है। इन चुनौतियों तुलना में, वर्तमान में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता नगण्य है।
- सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में भी तेजी से बदलाव हो रहा है, इसलिए निर्माण फर्म के लिए पर्याप्त धन के बिना उपयुक्त प्रौद्योगिकी के साथ बने रहना मुश्किल है।
- एक निर्माण इकाई को बिजली और पानी की लगातार आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ग्रीनपीस के अनुसार, दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता TSMC अकेले ताइवान की सालाना बिजली का 4.8% उपयोग करती है। जब ताइवान पिछले साल सूखे की चपेट में था, तो TSMC ने ट्रकों से पानी का आदेश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके निर्माण में कोई व्यवधान न हो। जब सरकार ने चिप निर्माताओं को पानी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी, तो इससे कंपनियों और किसानों के बीच तनाव पैदा हो गया। भारत जैसे देश में, बिजली और पानी की आवश्यकता और भी बड़ी बाधा है।
- सेमीकंडक्टर निर्माण में जहरीली गैसें और रसायन भी शामिल होते हैं जो ग्रीनहा. उस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होते हैं। एंटीमनी, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि जैसे फैब्रिकेशन इकाइयों से निकलने वाले खतरनाक कचरे के निपटान का भी मुद्दा है।
- भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के क्षेत्र में विशेषज्ञता का भी अभाव है। सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में मानव संसाधन क्षमता भी भारत में सीमित है।
- सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों को बहुत विशिष्ट कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अर्धचालक निर्माण में शामिल कई रसायनों को भारत में आयात करने की आवश्यकता होती है।
- इस क्षेत्र में बाजार की मांग भी लगातार बदल रही है और बढ़ रही है, इसलिए इस बाजार की मांग को उत्पाद और मात्रा के मामले में बनाए रखना भी फर्मों के लिए मुश्किल है।

अवसर

जहां अनेक चुनौतियां हैं, वहीं सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में भारत के लिए पर्याप्त अवसर भी हैं।

- सेमीकंडक्टर्स की मांग लगातार बढ़ रही है। COVID महामारी ने लोगों को अपनी दैनिक आर्थिक और आवश्यक गतिविधियों के बड़े हिस्से को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए मजबूर कर दिया है, इस वजह से लोगों के जीवन में चिप-संचालित कंप्यूटर और स्मार्टफोन की मांग बढ़ी है।
- भारत में क्रमश: पश्चिमी देशों और चीन की तुलना में सस्ते श्रम और डिजाइन प्रतिभाओं की उपलब्धता है।
- ऑटोमोबाइल जैसे संबद्ध क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देने के कारण, भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए एक बड़ा बाजार भी है। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2020 में $ 15 बिलियन की तुलना में 2026 तक $ 63 बिलियन को छूने का अनुमान है।
- सरकार का ध्यान इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय

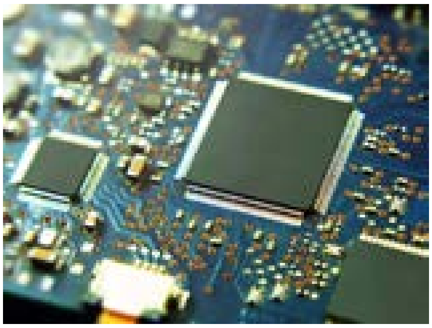

सहायता, लालफीताशाही में कमी,भूमि अधिग्रहण के लिए समर्थन और कर छूट के रूप में सहायता मिल रही है।

- चिप डिजाइनिंग क्षेत्र में मौजूदा विशेषज्ञता फैब्रिकेशन निर्माण इकाइयों के साथ-साथ पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना में भी रास्ता दिखाएगी।
- चीन और अमेरिका के बीच बढ़ता व्यापार युद्ध भी भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनने का अवसर प्रदान करता है।

सेमीकंडक्टर (अर्धचालक) - बेसिक्स

सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के गुण होते हैं। सेमीकंडक्टर्स कम तापमान पर बिजली के इंसुलेटर और उच्च तापमान पर बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं। वे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक सेमीकंडक्टर और बाह्य सेमीकंडक्टर। आंतरिक सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर्स का शुद्ध रूप है। शुद्ध क्रिस्टल में अशुद्धियों की एक छोटी संख्या के मिश्रण से बाह्य सेमीकंडक्टर तैयार किए जाते हैं।

सेमीकंडक्टर अपने दो महत्वपूर्ण गुणों के कारण इतने उपयोगी होते हैं। सबसे पहले, उनकी चालकता को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरे, वे एक यूनिडायरेक्शनल करंट दे सकते हैं। इसके अलावा, उनके पास छोटे आकार, कम बिजली की आवश्यकता, लंबे जीवन और उच्च विश्वसनीयता का भी लाभ है।

सेमीकंडक्टर्स की पीढ़ियां

- सेमीकंडक्टर्स की पहली पीढ़ी सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी है।
- सेमीकंडक्टर्स की दूसरी पीढ़ी गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम एंटीमोनाइड आदि से बनी है।
- सेमीकंडक्टर्स की तीसरी पीढ़ी सिलिकॉन कार्बाइड, गैलियम नाइट्राइड आदि से बनी है।

सेमीकंडक्टर्स के अनुप्रयोग

सेमीकंडक्टर्स लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर, सेल फोन आदि का हिस्सा हैं। इनका उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन में भी किया जाता है। वे बैंक एटीएम, ट्रेनों, इंटरनेट, वायरलेस संचार आदि के संचालन में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। वे नियमित उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे रेफ्रिजरेटर, एसी आदि के महत्वपूर्ण घटक हैं। वे नई तकनीकों जैसे कि सेल्फ-ड्राइविंग कार, 3 डी प्रिंटिंग, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) में भी उपयोगी हैं। । वे ऑटोमोबाइल और चिकित्सा उपकरण उद्योग की रीढ़ भी हैं।

आगे का रास्ता

हालांकि सरकार द्वारा उठाए गए कदम प्रशंसनीय हैं, लेकिन वे इस दिशा में पहले नहीं हैं। इस क्षेत्र में नीतिगत अस्थिरता के कारण पहले के प्रयास विफल रहे। अब सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेमीकंडक्टर इका. इयों को समर्थन देने की यह नीति निरंतर बनी रहे। सरकार को इस क्षेत्र के लिए एक रोडमैप तैयार करना चाहिए जो पहले चिप डिजाइनिंग क्षेत्र में प्रगति पर ध्यान दें, फिर पैकेजिंग क्षेत्र में जाएं और अंत में विनिर्माण क्षेत्र की ओर पदार्पण करे। राज्यों को वित्तीय स्थान प्रदान करने की भी आवश्यकता है ताकि वे अपनी सीमा के भीतर स्थापित सेमीकंडक्टर इकाई का समर्थन कर सकें। भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए क्वाड जैसे बहुपक्षीय समूह का उपयोग करना चाहिए। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योगों को कच्चे माल के पुनर्चक्रण पर ध्यान देना चाहिए। चूंकि विनिर्माण उद्योग को उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता होती है, विनिर्माण इकाइयों को भी जहां आवश्यक हो, स्वचालन और रोबोटिक्स को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण के क्षेत्र में स्वदेशी बौद्धिक संपदा अधिकार सृजन को बढ़ावा देना चाहिए और सुविधा प्रदान करनी चाहिए। अनुसंधान और कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, उद्योगों और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग और साझेदारी बढ़ाई जानी चाहिए।

निष्कर्ष

हर समस्या एक अवसर के साथ आती है। यह कथन पिछले साल सेमीकंडक्टर्स की भारी कमी के बारे में भी सही है। इस कमी ने भारत को सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए अभिनव तरीके विकसित करने के लिए प्रेरित किया। यदि ठीक से लागू किया जाता है, तो ये तरीके भारत को एक जरूरतमंद आयातक से अर्धचालकों के निर्यात केंद्र में बदल सकते हैं।

NOTES

भारत में वनाग्नि और वनवासी समुदाय

चर्चा में क्यों?

हाल के दिनों में, पूरे भारत और दुनिया भर में वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि हुई है। राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व और उड़ीसा में सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य जैसे प्रसिद्ध संरक्षण क्षेत्र भी इन वनाग्नियों से प्रभावित हुए हैं। इन घटनाओं के संबंध में, वनाग्नियों से निपटने में वन-निवासी समुदायों की भूमिका पर बहस चल रही है।

वनाग्नि की संभावना वाले क्षेत्र

पिछली रिकॉर्ड की गई घटनाओं के आधार पर, पूर्वोत्तर और मध्य भारत क्षेत्रों के जंगल इन आग के लिए सबसे संभावित क्षेत्र हैं। असम, मिजोरम और त्रिपुरा के जंगलों की पहचान वनाग्नि के लिए 'अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों' के रूप में की गई है। आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के जंगलों को वनाग्नि के लिए 'अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वनाग्नि के कारण

वनाग्नि प्राकृतिक और मानव जनित दोनों का. रकों के कारण होती है।

- प्राकृतिक कारणों में, जलवायु प. रवर्तन प्रमुख कारकों में से एक है। लंबी अवधि, बढ़ती तीव्रता, उच्च आवृत्ति और अत्यधिक ज्वलनशील, आग को जलवायु परिवर्तन से जोड़ता जा रहा है। भारत में वनाग्नि का संबंध ऋतुओं से भी है। ये आग सबसे अधिक मार्च और अप्रैल के दौरान रिपोर्ट की जाती है जब जमीन में बड़ी मात्रा में सूखी लकड़ी, मृत पत्ते, स्टंप, सूखी घास और खरप. तवार होते हैं जो ट्रिगर मिलने पर जंगल को आग की लपटों में डाल सकते हैं। अत्यधिक गर्मी और सूखापन के साथ-साथ शाखाओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न घर्षण भी वनाग्नि को भड़का सकता है। वनाग्नि के होने में, मिट्टी में नमी की कमी भी एक प्रमुख कारक है। उत्तराखंड में, कम मानसून का मौसम जिसके कारण मिट्टी की नमी में कमी आई है, ने हाल की आग की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिजली और आंधी भी वनाग्नि में भूमिका निभाते हैं।
- मानवजनित कारणों में, गैर- जानबूझकर और जानबूझकर दोनों कारक हो सकते हैं। कभी-कभी सिगरेट की बट से एक छोटी सी चिंगारी और जलाई हुई माचिस की तीली वनाग्नि का कारण बन सकती है। ये आग महु. आ के फूलों को इकट्ठा करने जैसे वन संसाध नों के पारंपरिक उपयोग के दौरान भी लग सकती है। ये वन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों का परिणाम भी हो सकती हैं। पारंपरिक कृषि विधियों जैसे कि स्थानांतरित खेती के दौरान खेती के लिए भूमि की सफाई से भी आग लग सकती है।

वनाग्नि को नियंत्रित करने में कठिनाइयाँ

जंगल के इलाके और उस तक पहुँच के मुद्दे के कारण वनाग्नि को नियंत्रित करना मुश्किल है। पीक फायर सीजन में स्टाफ की कमी भी चिंता का विषय है। घने जंगल में आग के प्रकार के आधार पर समय पर ईंधन और उपकरण जुटाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। चूंकि पानी से लदे भारी वाहनों को घने जंगल में ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए अधिकांश अग्निशमन मैन्युअल रूप से ब्लोअर का उपयोग करके शुरू किए जाते हैं। हाल ही में, हेलीकाप्टरों का उपयोग भी अग्निशमन के लिए किया जा रहा है। हवा की गति और दिशा भी अग्निशामकों के लिए एक चुनौती पेश करती है।

वनाग्नि के प्रभाव

मानव जीवन के नुकसान के अलावा, वनाग्नि के अन्य प्रतिकूल प्रभाव भी होते हैं। वन आवरण के नुकसान से कार्बन सिंक को नुकसान होता है। भारत में, ईंधन, बांस, चारा और छोटी लकड़ियों के लिए जंगलों पर निर्भर करोड़ों लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वनाग्नि के दौरान उत्पन्न गर्मी पशु आवासों को नष्ट कर देती है, जिससे जैव विविधता कम हो जाती है। आग से मिट्टी की नमी और उर्वरता भी प्रभावित होती है। आग से बचने वाले पेड़ों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं। वनाग्नि संरक्षण उपायों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में हाल ही में लगी आग ने इसके बाघ संरक्षण उपायों को प्रभावित किया है। वनाग्नि वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों की रिहाई का कारण भी बन रही है। वनाग्नि पर्यटन क्षमता को भी कम करती है।

वनवासी समुदायों की भूमिका

सदियों से, वनवासी समुदायों ने अपने अस्तित्व की जरूरतों और प्राकृतिक दुनिया के उत्थान के बीच संतुलन को बनाए रखा है। उनकी पारंपरिक प्रथाएं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के एक बड़े हिस्से के स्वास्थ्य का प्रमुख कारण हैं। हालाँकि, भारत में, हम औपनिवेशिक वानिकी मॉडल से आगे नहीं बढ़े हैं, जिसने पारंपरिक समुदायों को अपराधियों के रूप में माना और वन संसाधनों को उनसे बचाने की कोशिश की। यह औपनिवेशिक मॉडल स्वतंत्रता के बाद की अवधि में एक किले-शैली के संरक्षण मॉडल में परिवर्तित हो गया था जिसने वन और स्थानीय समुदायों के बीच एक अवरोध बना

दिया था। जबकि दुनिया वनाग्नि को रोकने के लिए समय-समय पर नियंत्रित अग्नि के लाभों के पारंपरिक सामुदायिक ज्ञान से अवगत हो रही है, भारत में अभी भी जानबूझकर जंगलों को जलाना एक अपराध है। वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के अनुसार, आरक्षित वन में आग लगाना अवैध है और यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ऐसा करता पाया जाता है, तो वह उस क्षेत्र में चारागाह और वन उपज के सभी अधिकार खो सकता हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 30 में भी आग लगाने पर रोक है। अब यह सर्वविदित है कि कम से मध्यम तीव्रता की आग बड़ी ज्वालाओं के लिए ईंधन को कम करती है और उन पौधों के अंकुरण में सहायता करती है जिनके बीजों को अंकुरित होने के लिए आग की आवश्यकता होती है। यह आग की तीव्रता को कम करने के लिए अनियंत्रित लैंटाना प्रसार को भी रोकता है। हाल के दिनों में वनाग्नि जैसी आपदाओं को रोकने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, इन समुदायों के सामुदायिक वन अधिकारों को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत मान्यता दी गई है। वे वनाग्नि को रोकने में सहयोगी बन रहे हैं। उदाहरण के लिए सिमलीपाल में आदिवासी लोग पिछले साल आग से जूझने में मदद कर रहे थे और इस साल महिला स्वयं सहायता समूह फायर लाइन बना रहे हैं।

सरकार द्वारा किए गए उपाय

2004 से, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) ने वास्तविक समय में जंगल की आग की निगरानी के लिए वन फायर अलर्ट सिस्टम विकसित किया है। सरकार ने सभी हितधारकों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए वनाग्नि पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना भी तैयार की है।

आगे का रास्ता

वनाग्नि से निपटने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

- वनाग्नि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और मानचित्रण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह प्रावधान प्रबंधन हस्तक्षेपों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने, संसाधनों के आवंटन और आग को नियंत्रित करने के उपायों की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। इन संवेदनशील क्षेत्रों की किसी भी बदलाव के हिसाब से तैयारी के लिए हर पांच साल में कम से कम एक बार समीक्षा की जानी चाहिए।
- कई वनाग्नियां मानव निर्मित होती हैं और लोगों के आर्थिक और आजीविका के मुद्दों से संबंधित हैं। उन लोगों को वनाग्नि के खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए, स्कूल अभियानों, रेडियो और टीवी अभियानों के साथ-साथ संगीत समारोहों के माध्यम से छात्रों, किसानों, महिला समूहों, पशुपालकों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों पर विशेष रूप से लक्षित प्रभावी संचार रणनीतियों का उपयोग किया जाना चाहिए। वनवासी समुदायों को क्षमता निर्माण के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार करना चाहिए।
- जल और नमी संरक्षण, वन तल बायोमास प्रबंधन और खरपतवार प्रबंधन के माध्यम से वनाग्नि के प्रति लचीलापन बढ़ाया जाना चाहिए।
- वनाग्नि के लिए तैयारियों में जंगल में आग का जल्द पता लगाना और सतर्क करना, महत्वपूर्ण संसाधनों और संपत्तियों के स्थान का डिजिटलीकरण, फायर लाइनों की स्थापना और नियंत्रित अग्नि का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- मौजूदा आग को दबाने के लिए, वनाग्नि के अलर्ट के बाद आकस्मिक प्रतिक्रिया की संस्कृति होनी चाहिए जिसके तहत आग बुझाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाए। इस संस्कृति को सभी स्तरों पर प्रशिक्षण, अग्निशमन से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है।
- नुकसान के आकलन, कारणों की उचित जांच और आग प्रभावित क्षेत्रों की बहाली के माध्यम से प्रभावी पोस्ट-फायर प्रबंधन होना चाहिए।

NOTES

भारत में पेट्रोलियम तेल के दाम में हो रही वृद्धि और मुद्रास्फीति

चर्चा में क्यों?

यूक्रेन युद्ध ने वर्तमान तेल के दाम में हो रही वृद्धि को बनाए रखा है और साथ ही खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया है। क्या यह संयोजन लगातार भ. ारतीय मुद्रास्फीति में वृद्धि को उत्पन्न करेगा जैसा कि 2010 के दशक में हुआ था?

कच्चे तेल के दाम में वृद्धि और मुद्रास्फीति के विभिन्न चरणः-

- 1970 के दशक में तेल के दाम में वृद्धि ने उच्च मुद्रास्फीति के एक विश्वव्यापी मुकाबले को ट्रिगर किया था, लेकिन बाद में कीमत में होने वाली वृद्धि,अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति के बिना ही नियंत्रित हो गई थी।
- 70 के दशक के अंत में, 90 के दशक के अंत में और 2002-2005 में कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि हुई थी, लेकिन भारत सहित दुनिया ने इसे बेहतर तरीके से प्रबंधित किया था।
- इनके प्रबंधन में खुलापन, सस्ता आयात, अधिक लचीली मजदूरी और तेल पर कम निर्भरता के साथ-साथ बेहतर मौद्रिक नीति शामिल थे।
- उस समय उत्पादकता बढ़ रही थी और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियां(जो वर्तमान में हैं) कीमत में हो रही वृद्धि में अनुपस्थित थे।
- हालांकि 2002 में तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद विश्व खाद्य कीमतों में वृद्धि शुरू हो गई थी, भारतीय खाद्य मुद्रास्फीति आंशिक रूप से कम रही थी, क्योंकि इस अवधि में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में केवल मामूली वृद्धि हुई थी। साथ ही खाद्य स्टॉक एक सर्वकालिक निचले स्तर पर गिर गया था।
- लेकिन 2006-07 से एमएसपी तेजी से बढ़े थे, क्योंकि खरीद कीमतों पर लगाया गया अनुशासन खत्म कर दिया गया था।
- 2010-11 में खाद्य भंडार और मुद्रास्फीति दोनों चरम पर पहुंच गए थे।
- तेज नीति के नेतृत्व में मांग संकुचन ने तेल-कीमतों में वृद्धि के लिए उत्पादन वृद्धि को कम कर दिया, साथ ही खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति कम रही इस कारण मुद्रास्फीति को कम करने में सफल रहे थे।

तेल की कीमत के झटके और वैश्विक वित्तीय संकट :-

- भारत में, मुद्रास्फीति की ऐतिहासिक उच्च एकल-अंकीय दर 90 के दशक के अंत में आधी हो गई थी, लेकिन 2008 में दोहरे अंकों में पहुंच गई, जैसे कि 70 के दशक की शुरुआत में तेल के दाम में वृद्धि के दौरान हुई थी।
- उस तेल की कीमत की वृद्धि के झटकों ने वैश्विक वित्तीय संकट को पूर्वनिर्धारित किया और इसके घटने के बाद, तेल की कीमतें फिर से बढ़ीं और 2014 तक एक उच्चता के साथ नियत रहीं।
- इस तरह के दाम में वृद्धि क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में लागत को बढ़ाते हैं, लेकिन निरंतर मुद्रास्फीति के लिए, मजदूरी को भी बढ़ाना पड़ता है। अधिक संभावना होती है कि इससे खाद्य कीमतें भी देश में बढ़ती हैं।
- चूंकि उच्च इनपुट मूल्यों ने खाद्य मुद्रास्फीति को बनाए रखा है, जबकि भारत संयोजन का सामना करने में असमर्थ था।
- भोजन, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के खपत बास्केट में कम हिस्सा रखता है।
- प्रशासित घरेलू ईंधन की कीमतें न तो बढ़ीं और न ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के रूप में गिरी, लेकिन संचयी भारतीय ईंधन मुद्रास्फीति वैश्विक स्तर से बहुत अधिक हो गई।
- इस शाफ्ट प्रभाव(तंजबीमज र्मिमिबज) ने भारतीय मुद्रास्फीति में योगदान दिया। यह कम पुरानी मुद्रास्फीति बनाने वाले अन्य लागत-पुश कारकों में से एक था।
- 2005 से मामूली गिरावट के बाद, धीरे-धीरे कीमतें बाजार चालित हो गईं, परन्तु 2015 में अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बड़ी गिरावट के बाद भी भारत में कीमतें अधिक थी क्योंकि भारत में इन पर लगने वाले करों को बढ़ाया गया था।
- फिर भी, इसने देश के मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दिया।

क्या इतिहास खुद को दोहराएगा?

- युद्ध जारी है, लेकिन विकसित होती भारतीय विविधता का मतलब है कि कोई भी चुनौती काउंटर के रूप में भारत के लिए कुछ अवसर पैदा करेगी। ऊंची कीमतों (आयात निर्यात शुल्क) से फार्म लॉबी को एमएसपी बढ़ाने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, वर्तमान गेहूं की कीमतों में वृद्धि घरेलू कीमतों में वृद्धि कर रही है, लेकिन यह अस्थायी है।
- अधिकांश भारतीय कृषि उत्पाद की कीमतें उच्च सीमा तक पहुंच गई हैं या ऊपर हैं, यह एमएसपी में वृद्धि को सीमित करती हैं।
- कृषि उत्पादकता, विपणन अवसंरचना और समन्वय में सुधार के रूप में निर्यात में वृद्धि हुई है।

आपूर्ति पक्ष क्रियाओं का प्रभाव :-

- आपूर्ति-पक्ष क्रियाएं लागत-पुश कारकों को कम कर रही हैं।
- यह एक स्थायी लागत-पुश को एक अस्थायी झटके में परिवर्तित करता है।
- अमेरिका में, अतिरिक्त राजकोषीय प्रोत्साहन और तंग श्रम बाजारों के कारण कोविड आपूर्ति-पक्ष की बाधाएं स्थायी होती जा रही हैं।
- इसलिए, भारतीय मुद्रास्फीति अमेरिका से

अलग है और इस कारण भारत को इतिहास का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

भारत में मुद्रास्फीति व्यवस्था का पालन किया गया:-

- भारत अब एक लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यी. करण व्यवस्था के तहत है।
- ब्याज की वास्तविक दरों को संतुलन के पास रखने के लिए नीतिगत दरों में वृद्धि करनी होगी क्योंकि मुद्रास्फीति के सहिष्णुता बैंड से लगातार ऊपर जाने की उम्मीद बताई जा रही है।
- प्रतिक्रिया का यह आश्वासन मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करने में मदद करता है।

आपूर्ति में झटके की स्थिति :-

(आपूर्ति के झटकों के तहत, अवस्फीति से उत्पादन को कम करना पड़ता है।

(यह स्थिति विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि भारत में राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता से कम है और भारत में बेरोजगारी भी अधिक है।

आउटपुट स्तर को कैसे बनाए रखने रखा जाए ?

(उत्पाद शुल्क करों में एक काउंटर-चक्रीय गति, विशेष रूप से ईंधन पर, यह उत्पादन में होने वाली कमी को कम कर सकता है।

(यदि करों में वृद्धि केवल तब होती है जब अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें गिरती हैं, जैसा कि 2014 और 2020 में हुआ था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें बढ़ने पर गिरावट नहीं आती है, तो यह पहले के शाफ्ट को फिर से लागू करेगा, जिससे कास्ट क्रीप(बवेज बतममच) की स्थिति होगी और भाररतीय मुद्रास्फीति को अंतरराष्ट्रीय स्तर से अधिक रखने और मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करना मुश्किल हो जाएगा।

(विश्व तेल की कीमतें 2021 की शुरुआत में और 2014 के अंत की तुलना में कम थीं। लेकिन भारतीय खुदरा कीमतें अधिक थीं।

कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव :-

- अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स आधुनिकी करण अधिनियम के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें अत्यधिक अस्थिर रही हैं, जिसने बाजार-व्यापार की स्थिति की सीमा को आसान कर दिया, अन्य विनियमों के बीच, बाजार के उतार-चढ़ाव को बढ़ा दिया

- ब्रेंट ऑयल 2008 के मध्य में $132 से लेकर तेज उतार-चढ़ाव के साथ जनवरी 2016 में $30 तक, रहा। कोविड के समय यह $18 तक के स्तर तक भी गया परन्तु यह लंबे समय तक नहीं रहा।
- यूक्रेन के बाद, यह फिर से $130 से ऊपर थोड़ा ऊपर उठा। भिन्नता का मासिक गुणांक 2000 से पहले 25 और उसके बाद 42 रहा था।
- इस तरह की अस्थिरता आयातक और उत्पादक दोनों देशों को आहत करती है और इसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाए जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष :-

(राज्यों के साथ-साथ केंद्र के लिए तेल करों में कुछ काउंटर चक्रीयता पेश करने के लिए एक सूत्र, जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों में थ्रेसहोल्ड से जुड़ा हुआ है, पहले के शाफ्ट पर वापस जाए बिना अत्यधिक अस्थिरता को कम करेगा जिसने लागत को बढ़ा दिया।

(यह मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण स्थापित करने, केंद्र और राज्यों के बीच गतिरोध के कारण देरी को कम करने और भारत की जीएसटी प्रणाली में ईंधन को शामिल करने की दिशा में एक कदम होने में मदद करेगा।

(सरकारों के पास अभी भी इच्छानुसार तेल पर करों को बदलने की शक्ति होगी, लेकिन तेल करों का कुछ हिस्सा स्वचालित रूप से वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ गिर जाएगा और इन कीमतों में गिरावट आने पर बढ़ जाएगा। इन बदलावों को केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाएगा।

NOTES

वैश्विक राजनीति के केंद्र में भारत

सन्दर्भ

वर्तमान विश्व में हो रही गतिविधियों यथा रूस- यूक्रेन युद्ध, जलवायु संकट, आतंकवाद, कोविड का निवारण इत्यादि में भारत की भूमिका में वृद्धि भारत को वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला रही है।

परिचय

पिछले कुछ समय में भारत के वैश्विक कद में निरंतर वृद्धि हो रही है। योग, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद तथा संगठित अपराध, जैसे मुद्दों पर भारत की नीतियों को पहले भी महत्व दिया जाता था इसके साथ ही साथ आसियान, दक्षिण -एशिया तथा हिन्द-महासागर में भारत का क्षेत्रीय महत्व था। परन्तु रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत का महत्व क्षेत्रीय से बढ़कर वैश्विक हो गया। इस सन्दर्भ में चीन, मैक्सिको, ब्रिटेन और रूस के विदेश मंत्रियों ने भारत का दौरा किया तथा डेनमार्क, यूक्रेन, अमेरिका तथा ब्रिटेन के द्वारा निरंतर भारत से इस युद्ध में अपनी कूटनीति के प्रयोग की बात की जा रही है। यह स्थितियां भारत के बढ़ते हुए राजनैतिक कद का सूचक हैं जो भारत को वैश्विक राजनीति के केंद्र मे ला रही हैं।

भारत को वैश्विक राजनीति के केंद्र में रखने वाले कारक :-

विचारधारा :-

भारत के द्वारा सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुमबकम, के प्राचीन विचारधारा के साथ-साथ लोकतंत्र, पंचशील तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की आधुनिक विचारधारा का प्रयोग किया जाता है जो वैश्विक शान्ति तथा संवृद्धि हेतु श्रेयस्कर है।

भौतिक अवस्थिति :-

भारत की अवस्थिति उसे हिन्द महासागर में स्वाभाविक बढ़त प्रदान करती है। वर्तमान समय में वैश्विक राजनीति यूरोप-अटलांटिक क्षेत्र से हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में शिफ्ट हो रही है। यहां पर भारत की स्वाभाविक बढ़त के कारण सभी बड़ी शक्तियां भारत के साथ बेहतर सम्बन्ध स्थापित करना चाहती हैं। अत: हम यह कह सकते हैं कि भारत की भौतिक अवस्थिति उसे वर्तमान वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला रही है।

युवा जनसँख्या तथा मानव संसाधन :

भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसँख्या का प्रतिनिधित्व (लगभग 17 %) करता है। इसके साथ भारत के जनसँख्या की औसत आयु 29 वर्ष है इसीलिए जहाँ एक तरफ भारत एक बड़ा बाजार है वहीं भारत मानव संसाधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। वर्तमान समय की उपभोक्तावादी संस्कृति तथा पूंजीवादी विचारधारा में इन दोनों (बाजार तथा श्रम आपूर्ति) का ही अधिक महत्व है। आज लगभग सभी महत्वपूर्ण विकसित देश भारत में निवेश करना चाहते हैं वहीं भारतीय डायसफोरा लगभग सभी देशो में निवास करते हैं। ये भारत की वैश्विक स्थिति को और अधिक मजबूत करता है।

राजनय (डिप्लोमेसी):-

वर्तमान समय में भारत की कूटनीति विश्व में सर्वोत्तम है। जहाँ एक तरफ भारत वैक्सीन, अंतरिक्ष तकनीक तथा पर्यटन के द्वारा सॉफ्ट डिप्लोमेसी का उपयोग कर रहा है वहीं भारत की सैन्य ताकत के कारण आसियान, हिन्द-प्रशांत तथा दक्षिण एशिया में प्रमुख शक्ति है जो भारत की हार्ड पावर डिप्लोमेसी को मजबूत करती है। इस प्रकार भारत एक मजबूत कूटनीतिक आधार बना चुका है।

अन्तर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता

वर्तमान समय में भारत पर अन्य देशो के विश्वास में वृद्धि हुई है। डोकलाम मुद्दे पर भारत की दृढता, नो फर्स्ट यूज के साथ परमाणु शक्ति सम्पन्नता, अंतरिक्ष में भारत के सफल अभियान, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत की नीति की सभी देश प्रशंसा कर रहे हैं। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश भारत को नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखते हैं तथा आतंकवाद तथा संगठित अपराध के विरुद्ध भारत के प्रयासों को सम्पूर्ण विश्व में मान्यता मिली है (उदाहरणस्वरूप मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करना) जो भारत पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को बढ़ाता है।

अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में महत्व

वर्तमान समय में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का अस्थायी सदस्य है। कई देश लगातार भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए मांग उठा रहे हैं जिनमें ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देश भी सम्मिलित हैं। भारत सदैव अंतर्राष्ट्रीय विधियों का पालन करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के नियमों को देश में लागू करता है। भारत एनएसजी की सदस्ता का प्रयास कर रहा है इसके अतिरिक्त भारत लगभग सभी महत्वपूर्ण संस्थाओ का अंग है। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा मानवाधिकार आयोग के प्रमुख वित्त प्रदाताओं में एक है। संयुक्त राष्ट्र के अभियानों (सीरिया तथा अन्य) में भारतीय सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ संतुलित मापदंड

भारत जहाँ एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में

बने क्वाड (ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत तथा अमेरिका) संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत एससीओ (रूस तथा चीन के नेतृत्व में निर्मित संगठन) का सदस्य भी है। भारत अमेरिका तथा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सहित सम्पूर्ण यूरोप से अपने बेहतर सम्बन्ध बनाये हुए हैं वहीं भारत इन देशो के अनुरोध करने के उपरांत भी लगातार रूस के साथ व्यापार कर रहा है। यह स्थितियां भारत के संतुलित मानदंड को दिखती हैं।

इसके साथ ही फिलिस्तीन तथा इजराइल के साथ सम्बन्धो में भी भारत ने संतुलित विदेश नीति रखी।

स्वतंत्र विदेश नीति

भारत ने सदैव स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया है। शीतयुद्ध में भी भारत पूंजीवादी खेमे तथा साम्यवादी खेमे से दूर रहा तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बन गया। भारत ने कई बार भीषण अमेरिकी दबाव का सामना किया परन्तु भारत ने परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाये रखी जो आज भी दिखता है। आज अमेरिका तथा ब्रिटेन भारत पर लगातार रूस से व्यापार बंद करने हेतु कह रहे हैं परन्तु भारत ने रूस से रुबेल-रुपया पद्धति में व्यापार जारी रखा है। इस व्यापार के द्वारा भारत "ऊर्जा सुरक्षा" सुनिश्चित कर रहा है।

किन क्षेत्रो में अभी और अधिक प्रयास की आवश्यकता है :-

यद्यपि भारत वैश्विक राजनीति के केंद्र में है परन्तु कुछ ऐसे क्षेत्रक हैं जहाँ भारत को अभी सुधार की आवश्यकता है। वे निम्नवत हैं -

- भारत के द्वारा अन्य देशों में किये जा रहे निवेश परियोजनाओं में प्राय: विलम्ब हो जाता है। आईएनएसटीसी परियोजना, श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह परियोजना, बांग्लादेश में निवेश इत्यादि में विलम्ब के कारण भारत की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है।
- भारत को अभी भी आर्थिक स्तर पर अत्यधिक प्रगति की आवश्यकता है। यदयपि भारत पीपीपी के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है परन्तु भारत के पास अपनी विशाल जनसँख्या भी है जिसके फल. स्वरूप भारत में राजकोषीय घाटा बना रहता है तथा भारत अन्य देशों में चीन तथा अमेरिका के समान निवेश नहीं कर पाता।
- भारत के आंतरिक घटनाओं के कारण भी कई बार वैश्विक निंदा का सामना करना पड़ता है। यथा अनुच्छेद 370 हटाने पर यूरोपीय संसद तथा ओआईसी ने भारत की निंदा की थी।
- कई मामलो में स्पष्ट निर्णय न लेना भी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्रभावित करता है जैसे म्यांमार, अफगानिस्तान में तत्ख्तापलट पर भारत के उदासीन रूख ने भारत को आलोचना का पात्र बनाया था।
- चीन की बढ़ती शक्ति तथा चीन के साथ सीमा विवाद भारत की गति को अवरोधित करता है। चीन को कूटनीतिक रूप से परास्त करना भारत के लिए दुरूह है।

निष्कर्ष

- विश्व में भारत का लगातार बढ़ता कद भारत पर उत्तरदायित्व भी आरोपित करता है। हालाँकि अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका जैसे कई अन्य देशो में मानवीय सहयोग, डोकलाम में भूटान के लिए स्टैंड लेना, जलवायु परिवर्तन पर विकासशील तथा अविकसित देशो की बात को प्रभावी ढंग से रखने से यह प्रतीत होता है कि भारत अब क्षेत्रीय शक्ति से वैश्विक नेतृत्वकर्ता की तरफ बढ़ रहा है । अंतत: हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान स्थितियों में भारत वैश्विक राजनीति के केंद्र में है परन्तु अभी विश्व की सर्वोच्च शक्ति बनने हेतु भारत को लंबा रास्ता तय करना है।

NOTES

न्यायपालिका तथा कार्यपालिका में टकराव

सन्दर्भ

हाल ही में हुए राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों तथा मुख्यमंत्रियों के सम्मलेन में कार्यपालि. का तथा न्यायपालिका में टकराव की स्थिति देखने को मिली है।

परिचय

हाल ही उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा राज्यों मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मलेन में भारत के प्रधानमंत्री तथा उच्चतम

न्यायालय मुख्य न्यायाधीश ने भी शिर. कत की। जहाँ एक तरह मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा कि लंबित मामलों के लिए काफी मात्रा में सरकार उत्तरदायी है क्योंकि आधे से अधिक मामलों में सरकार स्वयं से पक्षकार है। इस प्रकार मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपलिकीय अक्षमता के लिए काफी हद तक कार्यपालिका को दोषी ठहराय. ा। इसके उपरान्त प्रधानमन्त्री ने न्यायालय की भाषा तथा अन्य सुधारो से सम्बंधित वक्तव्य दिए। यह भारत में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के तनाव को प्रदर्शित करता है।

न्यायपालिका तथा कार्यपालिका में टक. राव के मुख्य कारण

- भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत में विधि बनाने का अधिकार विधायिका (संसद तथा राज्यविधान सभा) को है वहीं इन कानूनों का प्रवर्तन कार्यपालिका द्वारा सुनिश्चित कराया जाता है। जबकि संविधान ने ही इन कानूनों के व्याख्या (अनुच्छेद 13(२) से प्रेरित न्यायिक अवलोकन) का अधिकार न्यायपालिका को दिया है। अत: जब भी न्यायपालिका विधायिका अथवा कार्यपालिका द्वारा बनाये गये कानूनों को अनुचित ठहराती है तब न्यायपलिका तथा कार्यपलिका में टक. राव की स्थिति आ जाती है।
- न्यायपालिका तथा कार्यपालिका में टकराव का एक कारण न्यायिक अतिसक्रियता को भी माना जाता है। न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य न्यायलय का कार्यपालिकीय मामलो में हस्तक्षेप से है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि न्यायपालिका विधि निर्माता तथा प्रवर्तनकर्ता की भूमिका में आ गई थी। चुकी न्यायलय द्वारा दिए गए आदेश "विधि" के समकक्ष प्रभाव रखती है अत: कई मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप सहजता से हो जाता है। यह हस्तक्षेप समाज सुधार से सम्बंधित निर्णयों तथा पर्यावरणीय मामलो में प्राय: देखे जाते हैं।
- न्यायिक अक्षमता का एक मुख्य कारण लंबित मुकदमो की संख्या है। वर्तमान में 3.5 करोड़ से अधिक मामले न्यायपालिका में लंबित हैं। इन मामलो में आधे से अधिक में सरकार पक्षकार है। अत: न्यायपालिका यह तर्क देती है कि सरकार (कार्यपालिकीय) की अक्षमता के कारण न्यायपालिका की क्षमता प्रभावित होती है। भारत में न्यायिक अक्षमता का एक मुख्य कारण न्यायाधीशों की संख्या में भारी कमी है। लोअर कोर्ट्स में जजों की भर्ती सम्बंधित राज्य का लोकसेवा आयोग करता है। यह स्थितियां भी टकराव को जन्म देती हैं।
- भारत के लोकतंत्र में कार्यपालिका (निर्वाचित कार्यपालिका) के सदस्य विध ायिका के भी सदस्य होते हैं। भारत में "फर्स्ट पास्ट द पोल" व्यवस्था के कारण विधायिका सामूहिकता को अधिक महत्व देती है जबकि न्यायालय के निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता से प्रेरित होते हैं जैसा कि कई मामलो (आई. पी.सी. की धारा 377 तथा धारा 497 का विअपराधिकरण, सबरीमाला इत्यादि) में देखा जा चूका है। यह स्थिति भी न्यायपालिका तथा कार्यपलिका में टकराव को जन्म देती है।

- भारतीय संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे अधिकार (उदाहरण - शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, नि:शुल्क विधिक सहायता का अधिकार इत्यादि) वर्णित हैं जो वाद्योग्य नहीं हैं। परन्तु उच्च चतम न्यायलय ने इन अधिकारों में से कई अधिकारों को भाग -3 के वादयोग्य अधि कारों में एक अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार) के अन्तर्गत व्याख्यित कर दिया है उदाहरणस्वरूप - एमसी मेहता मामले में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 का अंग माना गया। यह भी न्यायिक सक्रियता को प्रदर्शित करता है।

- हाई-प्रोफाइल मामलों में यह टकराव और अधिक स्पष्ट हो जाता है। उदाहरणस्वरूप हाल ही में लखीमपुर मामले के आरोपी की जमानत के उपरान्त उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने इस मामले को आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा तब उच्चतम न्यायलय ने इस बाबत राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। ध्यातव्य हो कि इस मामले में सम्बन्धित्त आरोपी राज्य सत्तारूढ़ दल का प्रभावशाली सदस्य है।

क्या यह टकराव आवश्यक है ?

- भारत का संविधान "शक्ति के पृथकक्करण" के सिद्धांत को मान्यता देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य को निर्देशित करता है।
- भारत का संविधान विधायिका के कुछ कार्यों (विशेषाधिकार से सम्बंधित मामले, सिविल मामलो में साक्ष्य के रूप में उपस्थित होने से छूट) तथा कार्यपालिका के कुछ कार्यों (मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह, दल- बदल तथा धन विधेयक) को भी न्यायपलिका से संरक्षण प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ वह न्यायपालिका को भी पर्याप्त स्वायत्ता (संविधान के अंतिम व्याख्याकर्ता , शक्ति के पृथकक्करण, वेतन तथा भत्तों को संचित निधि पर भारित व्यय) प्रदान करता है।
- साथ संविधान विधि निर्माण का अधिकार विधायिका, विधि प्रवर्तन का अधिकार कार्यपालिका तथा विधि की समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका को देकर शक्ति के संतुलन को सुनिश्चित कर निरंकुशता को रोकता है।
- इसके साथ ही यह तर्क दिया जाता है कि जब संविधान द्वारा न्यायपालिका को विधि की समीक्षा का कार्य दिया गया है ऐसे में यदि वह कार्यपालिका तथा विधायिका के साथ सहयोग करेगी तो वह उचित समीक्षा नहीं कर पाएगी।

आगे की राह

- यद्यपि संविधान ने शक्ति के पृथक्करण की व्यवस्था की है परन्तु यह कठोर स्तर पर नहीं है। कई मामलो यथा- न्यायिक भर्ती, भाषा में सुधार, लंबित मामलों में कमी, पर्यावरण सम्बन्धी इत्यादि में सुधार हेतु आवश्यक है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका एक दुसरे के साथ सहयोग करें।
- विभिन्न आयोगों, अधिकरणों तथा अर्ध-न्यायिक संस्थानों की दक्षता से यह स्पष्ट होता है कि कुछ विशेष मामलो में न्यायपालिका तथा कार्यपलिका का सहयोग लोकतंत्र के संस्थागत व्यवस्था को मजबूत कर सकता है।

- इसके साथ ही साथ न्यायपालिका के लिए आवश्यक है कि वह विधियों की समीक्षा करते समय अपनी भूमिका का भान रखे। इस सन्दर्भ में 2007 में दिए गए अपने निर्णय में ही उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि, "जजों को अपनी सीमा जान लेनी चाहिए तथा सरकार चलाने का प्रयास नही करना चाहिए।" इस मामले में न्यायलय ने न्यायाधीशों को न्यायिक संयम अपनाने का निर्देश दिया था।
- अत: यह आवश्यक है कि न्यायालय न्यूनतम अंतर-शाखा हस्तक्षेप के साथ न्यायिक समीक्षा करे तथा न्यायिक दक्षता को बढ़ावा दे।

निष्कर्ष

- कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को यह ध्यान देना होगा कि भारत में वे दोनों ही सुशासन स्थापित करने तथा लोकतंत्र को मजबूत करने के माध्यम हैं। अत: यदि दोनों के कार्यों से यदि निरंकुशता तथा हितों का टकराव (जैसा 1970 के दशक में प्राय: देखा जाता था) ही आता रहा तो यह लोकतंत्र को कमजोर कर निरंकुशता तथा अदक्षता को बढ़ावा देगा।
- यह सत्य है कि विधायिका तथा कार्यपालिका विधि निर्माण तथा उसके प्रवर्तन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं परन्तु उनके द्वारा विधि निर्माण में अपनाई गयी प्रक्रिया न्यायसंगत है या नहीं इसका निर्धारण न्यापालिका करती है। यह स्थिति यदयपि टकराव को जन्म देती है परन्तु यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अत: दोनों को अपनी सीमा के अंतर्गत संविधान द्वारा प्रदत्त कार्य को पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए।

NOTES

संक्षिप्त मुद्दे

राष्ट्रीय

1 किसान संकट सूचकांक

चर्चा में क्यों?

नाबार्ड एक ऐसा सूचकांक तैयार करने की योजना बना रहा है जो भारत के किसानों के विभिन्न स्तरों के तनाव को मापने में सक्षम होगा।

इसकी आवश्यकता क्यों है?

भारत में किसान आत्महत्या 2015 से बढ़कर 8,007 हो गई, जो पिछले वर्ष 5,650 थी, जो इस वर्ष राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 41.7 प्रतिशत की वृद्धि है। भारत में किसान के आत्महत्या करने का एकमात्र कारण वित्तीय तनाव ही नहीं है, आत्महत्याओं के पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलू भी हैं, जिन्हें आमतौर पर उपेक्षित किया जाता है। सूचकांक भारत के किसानों द्वारा सामना किए जा रहे बहुआयामी तनावों की गणना करने का एक उपाय है।

लैंसेट के एक अध्ययन के अनुसार, आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण मानसिक तनाव है, न कि आर्थिक तनाव जिसे कर्ज माफी और सब्सिडी से ठीक नहीं किया जा सकता है।

किसानों के सामने क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं?

फसल की विफलता, सूखा, बाढ़ और ऋणग्रस्तता भारतीय किसानों की आत्महत्याओं में सबसे अधिक कारक हैं।

वास्तविक समस्या ऋण की चक्रीयता को लेकर है। भारत में एक किसान कई विकृतियों से ग्रस्त है जो खेती के व्यवसाय को जोखिम भरा और अव्यवहारिक बना देता है। उत्पादन चक्र किसानों के लिए ऋणी नहीं होना असंभव बना देता है, और आय अस्थिरता उसके लिए कर्ज के चक्र से बाहर आना मुश्किल बना देती है, इससे किसान पर अत्यधिक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा होता है।

सूचकांक कैसे काम करेगा?

इन मुद्दों को हल करने के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) ने तेलंगाना, महाराष्ट्र में और पटियाला में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के साथ मिलकर काम किया है, जिसके तहत विशेषज्ञ किसानों के लिए एक तनाव सूचकांक और मनोवैज्ञानिक संसाधन सूचकांक (पीआरआई) तैयार करेंगे। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए एक "स्ट्रेस इंडेक्स" (एसआई) बनाएगा और आत्महत्या को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्राम स्तर के स्वयंसेवकों के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करेगा। इस सूचकांक को तैयार करने के लिए विभिन्न चरण होंगे-

पहला चरण- 1,000 'कमजोर' या संवेदनशील किसान परिवारों पर सर्वेक्षण किया जाएगा।

दूसरा चरण- इन किसानों से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग उनके तनाव के स्तर को मापने के लिए किया जाएगा और यह आकलन किया जाएगा कि क्या वे इसे संभालने के लिए मानसिक रूप से मजबूत हैं।

तीसरा चरण- व्यथित किसान आमतौर पर उच्च एसआई (तनाव सूचकांक) और निम्न पीएसआई (मनोवैज्ञानिक संसाधन सूचकांक) प्रदर्शित करते हैं जो तनाव से निपटने के लिए उनकी मानसिक शक्ति और लचीलापन का संकेत है।

चौथा चरण- पंजाब में लगभग 200 'पीयर सपोर्ट वालंटियर (पीएसवी)' और तेलंगाना और महाराष्ट्र में 100-100 अपने क्षेत्रों में संकटग्रस्त किसानों की पहचान करेंगे और उन्हें कोई भी गलत कदम उठाने से रोकने के लिए लगभग छह महीने की काउंसलिंग प्रदान करेंगे।

आगे की राह-

किसान संकट सूचकांक सही दिशा में एक कदम है। यह किसानों द्वारा सामना किए जा रहे बहुआयामी तनावों का आकलन करने में मदद कर सकता है। इस सूचकांक का उपयोग इन समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा और भारत के किसानों के बीच आत्महत्या के मामलों की संख्या में कमी आएगी।

NOTES

2 जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों-

जम्मू-कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) के लिए गठित परिसीमन आयोग ने 5 मई 2022 को अपनी रिपोर्ट पेश की है।

जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग के बारें में -

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 में 2001 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र (संसदीय और विधानसभा) में पुनर्समायोजन और विभाजन का प्रावधान है, ऐसे प्राधिकरण संसद द्वारा निर्धारित शक्तियों का लाभ उठाते हैं। एससी और एसटी आरक्षित सीटों के लिए अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के समान प्रावधान करते हैं। यह परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग अधिनियम पर आधारित एक वैधानिक निकाय है।

1. **अब तक चार बार**-1952, 1965, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग की स्थापना की जा चुकी है।

2. **वर्तमान स्थिति-** 1971 की जनगणना के अनुसार विधानसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की सीमा तय की गई है।

शक्ति

1) परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में किसी भी राज्य विधानसभा द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है।

2) इसकी रिपोर्ट को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

जम्मू कश्मीर के मामले में,

1) जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग, जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2019 पर आधारित था।

2) इसे 6 मार्च, 2020 को स्थापित किया गया था।

3) 20 जनवरी को अपनी प्रारंभिक मसौदा रिपोर्ट और 6 फरवरी को दूसरी और अंतिम रिपोर्ट दी।

3. **संघटन**

- उच्चतम न्यायालय के जज (सेवानिवृत्त) - रंजना प्रकाश देसाई
- मुख्य चुनाव आयुक्त
- मुख्य चुनाव अधिकारी
- 5 संसद सदस्य सहयोगी सदस्य के रूप में।

4. **प्रमुख सिफारिशें**

- कश्मीर में कुल सीटें → 47 (1 सीट जोड़ी गयी)
- जम्मू में 43 (6 सीटें जोड़ी गयी)
- आरक्षित सीट → एससी / एसटी के लिए 9 सीटें → राजौरी / पुंछ में 6 सीटें (उच्चतम एसटी जनसंख्या वाला क्षेत्र)

- राजौरी पुंछ को अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में मिला दिया गया है।

- श्रीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को बारामुल्ला में स्थानांतरित कर दिया गया।

a) समिति ने कश्मीर पंडितों के नामांकन (कम से कम) के लिए 2 आरक्षित सीटों की सिफारिश की है।

b) इसने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के लिए सीट आरक्षण के प्रावधान के लिए केंद्र से भी सिफारिश की, जो जम्मू और कश्मीर को प्रवास के बाद स्थानांतरित कर दिया।

प्रमुख मुद्दा

(1) पूरे देश में, 2026 तक परिसीमन पर रोक है लेकिन केवल जम्मू कश्मीर में नये राज्य के निर्माण के बाद परिसीमन को अनुमति दी गई है।

(2) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर परसीमन आयोग स्थापित किया गया है, न कि परिसीमन आयोग अधिनियम की धारा 200 सी के आधार पर, जैसा 2001 की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2026 के बाद की ताजा जनगणना रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक, 2002 वाला परसीमन मान्य होगा।

(3) जम्मू-कश्मीर अधिनियम के अंतर्गत परसीमन में एकमात्र मापदंड (धारा 60 (जेड)) (बी) के रूप में जनगणना को नहीं अपनाया गया है।

(4) जम्मू-कश्मीर अधिनियम अपने आप में विचाराधीन है।

(5) प्रारंभ में विचार था कि उत्तर पूर्व राज्य के लिए भी परिसीमन किया जाना चाहिए लेकिन फिर इस विचार को त्याग दिया गया।

परिसीमन - किसी देश में भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को विधायी निकाय वाले प्रांत में सीमित करता है।

NOTES

अंतरराष्ट्रीय

1 भारत-जापान : मित्रता के 70 साल

चर्चा में क्यों?
वर्ष 2022 में, जापान और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ है।

भारत-जापान संबंधों की पृष्ठभूमि -
जापान और भारत के बीच औपचारिक संबंधों की शुरुआत 1952 में हुयी । द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, बहुपक्षीय सैन फ्रांसिस्को शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बजाय, भारत ने जापान के साथ एक द्विपक्षीय शांति संधि करने का विकल्प चुना, यह देखते हुए कि जापान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में पुन: शामिल होने के लिए सम्मान और समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

यह लंबे समय से चली आ रही मित्रता की बुनियाद थी। लेकिन राजनयिक संबंधों की स्थापना से पहले भी, दोनों देशों के लोगों के बीच सद्भावना व्यापार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के गहरे सूत्र उपस्थित थे।
1951 में, जब भारत ने नई दिल्ली में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की, तो इसमें जापानी एथलीटों को भी आमंत्रित किया गया। यह उन पहले अवसरों में से एक था जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापानी ध्वज फहराया गया था, अर्थात वैश्विक पहलों में जापान ने आधिकारिक रूप से भाग लिया था।

70 वर्षों के बहुस्तरीय आदान-प्रदान के बाद, दोनों देशों के बीच के संबंध "विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी" में विकसित हुए और अब वे स्वाभाविक साझेदार बन गए हैं।
यह साझेदारी एशिया और उसके बाहर शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने में एक-दूसरे के योगदान के प्रति गहरे सम्मान पर आधारित है। दोनों एक "फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (एफओआईपी)" और विभिन्न अन्य वैश्विक मुद्दों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं।

दोनों का लोगों से लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक लंबा इतिहास है जिसकी जड़े छठी शताब्दी में तक जाती हैं। इसी काल में बौद्ध धर्म को जापान ले जाया गया और, 752 ई. में, एक भारतीय भिक्षु, बोधिसेना ने टोडाई -जी में महान बुद्ध प्रतिमा की स्थापना की, जो जापान के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है।

भविष्य के लिए लक्ष्य
70वीं वर्षगांठ की थीम "बिल्डिंग ए फ्यूचर फॉर अवर सेंचुरी" है। यही है वो मंत्र जो इस वर्ष संबंधों का मार्ग प्रशस्त करेगा।
एशिया में लोकतांत्रिक देशों के रूप में, दोनों वैश्विक शांति और समृद्धि में योगदान करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। दोनों देश समान मूल्यों और परंपराओं की नींव पर राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक हितों को साझा करते हैं।
भारत-जापान को नियम-आधारित, स्वतंत्र और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने के अपने प्रयास सतत रूप से जारी रखना चाहिए । दोनों देश साइबर सुरक्षा, बाह्य अंतरिक्ष और आर्थिक सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों / क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं।

आर्थिक संबंधों को बढ़ाया जा सकता है लंबे समय से, जापान भारत को सबसे बड़ा ओडीए (आधिकारिक विकास सहायता) प्रदाता रहा है। उनके सहयोग के सबसे हालिया उदाहरणों में से एक है मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना। जापान भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। दोनों देशों ने सामाजिक बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अन्य देशों में आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा दिया है। दोनों देशों की बढ़ती हुयी आर्थिक साझेदारी हिंद-प्रशांत की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ विश्व अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर सकती है।

हमारे संबंधों के लिए साहित्य, सिनेमा, संगीत, खेल और शिक्षाविदों सहित सांस्कृतिक आदान-प्रदान आवश्यक हैं, जिससे नागरिक-नागरिक संबंधों को और मजबूती मिल सके। भारत में जापानी सीखने वालों की संख्या दिनोंदिन तीव्र गति से बढ़ रही है।

कोरोनावायरस महामारी के बावजूद, दोनों देशों के संबंध निरंतर फल-फूल रहे हैं। भले ही इन-पर्सन इंटरैक्शन की संख्या प्रभावित हुई हो, लेकिन इसका किसी भी तरह से यह मतलब नहीं है कि संबंध कमजोर हो गए हैं। दोनों एक-दूसरे के संपर्क में रहने के लिए नए तरीकों के रूप में डिजिटल तकनीक का उपयोग करके महामारी के दौरान भी साझेदारी को मजबूत कर सकते हैं।

आगे की राह -
दोनों देश मिलकर न सिर्फ अपना भविष्य तय सकते हैं और संबंधों की 100वीं वर्षगांठ के लिए मील के पत्थर स्थापित करते हुए संबंधों को उससे भी कहीं आगे ले जा सकते हैं। भविष्य इस साझेदारी के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करता है।

2 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पर भारत का स्थान

चर्चा में क्यों?

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 180 देशों में 150 हो गई है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष-

रिपोर्ट में भारत को "मीडिया के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक" के रूप में वर्णित किया गया है। पिछले साल की रिपोर्ट में, भारत 142 वें स्थान पर था। उच्च प्रेस स्वतंत्रता वाले देशों के लिए शीर्ष तीन स्थान नॉर्वे (92.65 का स्कोर), डेनमार्क (90.27) और स्वीडन (88.84) को मिला है।

मोल्दोवा (40 वां) और बुल्गारिया (91 वां) ने सरकार में परिवर्तन के कारण प्रेस की स्वतंत्रता में भारी सुधार दिखाया है। इस रिपोर्ट ने रूस (155) और बेलारूस (153) सहित 28 देशों में स्थिति को "बहुत खराब" के रूप में वर्गीकृत किया है। प्रेस स्वतंत्रता के लिए दुनिया के 10 सबसे खराब देशों में म्यांमार (176 वां), चीन (175 वां), तुर्कमेनिस्तान (177 वां), ईरान (178 वां), इरिट्रिया (179 वां) और उत्तर कोरिया (180 वां) शामिल हैं। रिपोर्ट में मीडिया ध्रुवीकरण में दो गुना वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। मीडिया ध्रुवीकरण भी देशों के भीतर विभाजन को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच ध्रुवीकरण भी कर रहा है। रिपोर्ट में इस चीज पर ध्यान आकर्षित करवाया है कि लोकतांत्रिक समाजों के भीतर, "ओपिनियन मीडिया" के प्रसार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुष्प्रचार के कारण विभाजन बढ़ रहे हैं।

आरएसएफ क्या है और इस सूचकांक का उद्देश्य क्या है?

आरएसएफ एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है जिसका उद्देश्य मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसे संयुक्त राष्ट्र के साथ परामर्शी दर्जा प्राप्त है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो हर साल जारी किया जाता है, का उद्देश्य पिछले कैलेंडर वर्ष में 180 देशों में पत्रकारों और मीडिया को प्राप्त प्रेस स्वतंत्रता के स्तर की तुलना करना है।

देशों का आकलन और रैंक करने के लिए आरएसएफ द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली-

देशों को 0 से 100 के बीच अंक के आधार पर रैंक दी जाती है, जिसमें 100 प्रेस की स्वतंत्रता के उच्चतम संभव स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं और 0 सबसे खराब। पांच प्रासंगिक संकेतकों पर देशों का मूल्यांकन किया जाता है: राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा।

भारत के बारे में इंडेक्स का क्या कहना-

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया और मीडिया पर स्वामित्व की एकाग्रता यह सभी यह दर्शाती है कि प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकारों को पुलिस हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा घात लगाकर हमला करने और आपराधिक समूहों या भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों द्वारा घातक प्रतिशोध सहित सभी प्रकार की शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है।

राजनीतिक संदर्भ: मूल रूप से उपनिवेश विरोधी आंदोलन का एक उत्पाद, भारतीय प्रेस को काफी प्रगतिशील के रूप में देखा जाता था, लेकिन 2010 के मध्य में राजनीतिक नेताओं द्वारा मीडिया के स्वामित्व में वृद्धि के साथ चीजें मौलिक रूप से बदल गईं।

कानूनी संदर्भ: भारतीय कानून सैद्धांतिक रूप से सुरक्षात्मक है लेकिन सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों के खिलाफ मानहानि, देशद्रोह, अदालत की अवमानना और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे आरोपों का तेजी से उपयोग किया जा रहा है।

आर्थिक संदर्भ: मीडिया आउटलेट बड़े पैमाने पर स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों के साथ विज्ञापन अनुबंधों पर निर्भर करते हैं।

सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ: भारतीय समाज की विशाल विविधता, मुख्यधारा के मीडिया में बमुश्किल परिलक्षित होती है।

NOTES

पर्यावरण

1 सरकार द्वारा इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माताओं के लिए 5 वर्षीय पीएलआई का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

भारत ने पानी से हाइड्रोजन निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइजर्स के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू करने की योजना बनाई है।

सन्दर्भ :-

- हाइड्रोजन और अमोनिया को जीवाश्म ईंधन के स्थान पर भविष्य के ईंधन के रूप में परिकल्पित किया गया है।
- अक्षय ऊर्जा से ऊर्जा का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जैसे ईंधनों के उत्पादन से राष्ट्र की पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी ऊर्जा सुरक्षा की प्रमुख आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सकता है।
- यह पहल अक्षय ऊर्जा (आरई) उत्पादन को बढ़ावा देगी क्योंकि आरई हरित हाइड्रोजन बनाने में मूल घटक होगा।
- यह स्वच्छ ऊर्जा के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करेगा।

इलेक्ट्रोलाइजर्स का महत्व :-

- इसका प्रयोग हरित हाइड्रोजन की लागत को कम करने में किया जा सकता है।
- भारत को हरित हाइड्रोजन हब बनाने के लिए विभिन्न निजी कंपनियों ने पहले ही बड़ी योजनाओं की घोषणा कर दी है।
- सरकार इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देकर भारत को हरे हाइड्रोजन के उत्पादन का केंद्र बनाना चाहती है।
- सरकार का लक्ष्य 2030 तक हरित हाइड्रोजन की लागत को 1 डॉलर प्रति किलोग्राम तक कम करना है।

घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लाभ :-

- स्थानीय इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण को बढ़ावा देने की योजना, बढ़ती वैश्विक मांग और इलेक्ट्रोलाइजर की पर्याप्त आपूर्ति की चिंताओं से प्रेरित है।
- यूरोपीय संघ ने रूसी गैस की मांग को कम करने के लिए 2030 तक अपनी हरित हाइड्रोजन आपूर्ति को चौगुना करने की योजना बनाई है। इससे दुनिया भर में इलेक्ट्रोलाइजर्स की मांग 400GW से अधिक हो जाएगी, जबकि वैश्विक आपूर्ति केवल 70GW ही है।
- इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए पीएलआई योजना और ग्रीन हाइड्रोजन के उठाव को नियंत्रित करने वाले नियम, ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने और क्षेत्रक के विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

क्या आप राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के बारे में जानते हैं?

इस मिशन का उद्देश्य सरकार को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और भारत को हरित हाइड्रोजन हब बनाने में सहायता करना है। इससे 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने और अक्षय ऊर्जा क्षमता के संबंधित विकास में मदद मिलेगी।

मिशन की विशेषताएं :-

- ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया निर्माता वितरण कंपनी के साथ 30 दिनों तक अपनी गैर-उपभोग वाली अक्षय ऊर्जा को बैंक में रख सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस ले सकता है।
- वितरण लाइसेंसधारी अपने राज्यों में ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया के निर्माताओं को रियायती कीमतों पर अक्षय ऊर्जा की खरीद और आपूर्ति कर सकते हैं, जिसमें केवल खरीद की लागत, व्हीलिंग शुल्क और राज्य आयोग द्वारा निर्धारित एक छोटा सा मार्जिन सम्मिलित होगा।
- 30 जून 2025 से पहले शुरू की गई परियोजनाओं के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के निर्माताओं को 25 वर्षों की अवधि के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क की छूट दी जाएगी।
- ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के निर्माताओं को किसी भी प्रक्रियात्मक देरी से बचने के लिए प्राथमिकता के आधार पर ग्रिड से कनेक्टिविटी दी जाएगी।
- अक्षय ऊर्जा की खपत के लिए हाइड्रोजन/अमोनिया निर्माता और वितरण लाइसेंसधारी को प्रोत्साहन के रूप में अक्षय खरीद दायित्व (आरपीओ) का लाभ दिया जाएगा।
- व्यापार करने में सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए एमएनआरई द्वारा समयबद्ध तरीके से वैधानिक मंजूरी सहित सभी गतिविधियों को करने के लिए एक एकल पोर्टल स्थापित किया जाएगा।

निष्कर्ष :-

यह 14 वां क्षेत्र होगा जिसमें सरकार पीएलआई प्रदान कर रही है। इस क्षेत्र के लिए पीएलआई देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के अपने दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इस नीति के लागू होने से देश के आम लोगों को स्वच्छ ईंधन मिलेगा। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और कच्चे तेल का आयात भी कम होगा।

2 पक्षियों पर वैश्विक अध्ययन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित पर्यावरण संसाधनों की वार्षिक समीक्षा 'द स्टेट ऑफ द वल्ड्र्स बड्र्स' से पता चला है कि पक्षियों की 10,994 जीवित प्रजातियों में से 48% की आबादी घट रही है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष-

- मानव आबादी की निरंतर वृद्धि और खपत की प्रति व्यक्ति दरों में प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक प्राकृतिक आवासों का रूपांतरण और क्षरण होता है और परिणामस्वरूप जैव विविधता का नुकसान होता है।
- अध्ययन में पाया गया कि दुनिया भर में मौजूदा पक्षी प्रजातियों में से 5,245 या लगभग 48% आबादी में गिरावट के दौर से गुजर रही है जबकि 4,295 या 39% प्रजातियों में स्थिर रुझान हैं, लगभग 7% या 778 प्रजातियों में जनसंख्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
- अध्ययन बर्डलाइफ इंटरनेशनल के इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट के सभी पक्षियों के नवीनतम आकड़े लिए गए है, जो दर्शाता है कि 1,481 या 13.5% प्रजातियां वर्तमान में वैश्विक विलुप्त होने के खतरे में हैं।
- इनमें 798 प्रजातियों को संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया, 460 को लुप्तप्राय के रूप में और 223 को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया जबकि 52 प्रजातियों में डेटा की कमी है।
- अधिक संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियां (86. 4%) समशीतोष्ण (31.7%) की तुलना में उष्णकटिबंधीय में पाई जाती हैं।

पारिस्थितिक तंत्र में पक्षियों का महत्व-

पक्षी, पारिस्थितिक तंत्र में योगदान करते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव को लाभान्वित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर पक्षियों की कार्यात्मक भूमिका में परागणक, बीज-फैलाना, पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर, मैला ढोने वाले और शिकारी शा. मिल हैं।

एवियन जैव विविधता के नुकसान में योगदान देने वाले कारक-

- भू-आवरण और भूमि-उपयोग परिवर्तन।
- मानव आबादी और उपभोग की प्रति व्यक्ति दरों की निरंतर वृद्धि।
- पर्यावास विखंडन और क्षरण: विशेष रूप से उष्ण कटिबंध में।
- वैश्विक वृक्ष आवरण परिवर्तन।
- अकेले भूमध्य क्षेत्र में 11 से 36 मिलियन पक्षियों के मारे जाने या अवैध रूप से ले जाने का अनुमान है।
- विदेशी आक्रामक प्रजातियों और बीमारी ने देशी प्रजातियों को प्रभावित किया है।
- बुनियादी ढांचा और ऊर्जा की मांग
- प्रदूषण
- कृषि रसायन और दवा
- वैश्विक व्यापार टेलीकनेक्शन
- जलवायु परिवर्तन

आगे की राह-

पक्षी न केवल जैव विविधता को बनाए रखते हैं बल्कि स्थायी कृषि जैसे मानव प्रयासों का भी समर्थन करते हैं और अन्य जानवरों की वृद्धि में सहायता करते हैं। जंगली पक्षी और उनसे प्राप्त उत्पाद भी भोजन (मांस, अंडे) के रूप में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। अध्ययन के अनुसार किसी भी अन्य वर्गिकी समूह की तुलना में पक्षियों की सांस्कृतिक भूमिका शायद अधिक महत्वपूर्ण है। अपने प्रतीकात्मक और कलात्मक मूल्यों अतिरिक्त विदेशी पक्षियों को देखना भी लोगों का शौक रहा है इसलिए मानव जीवन पर आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, स्वास्थ्य और पर्यटन से संबंधित प्रभावों के कारण पक्षियों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

NOTES

विज्ञान एवं तकनीक

1 इसरो का शुक्रयान मिशन

चंद्रयान और मंगलयान इन दो बड़े अभियानों के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह यानि वीनस के लिए एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है। हालांकि ISRO ने इस मिशन की टा. इमलाइन की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लंबे समय से वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र और पृथ्वी जुड़वा ग्रह हैं और शुक्र पर भी एक समय पर पृथ्वी की तरह भरपूर पानी मौजूद था। इसके साथ शुक्र पर ऐसे सभी संसाधन मौजूद थे जिससे वहां जीवन पनप सके लेकिन समय के साथ शुक्र पर मौजूद सारा पानी खत्म हो गया अब शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका है और इसका वायुमंडल बेहद जहरीला और कोरोसिव है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) दिसंबर 2024 में एक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र के वातावरण और इसके सतह के नीचे मौजूद तथ्यों के बारे में अध्ययन करना है। इसके लिए मिशन के जरिए कई बिंदुओं पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा जिसमें शुक्र के सतह की जांच करना, सक्रिय ज्वालामुखियों का पता लगाना, लावा के बहाव की जानकारी जुटाना, सतह के निचले हिस्से की परतों की जांच करना, शुक्र ग्रह के ढांचे और आकार की बाहरी एवं आंतरिक संरचना की स्टडी, शुक्र ग्रह के वायुमंडल की जांच करना और सौर हवाओं से शुक्र ग्रह का संबंध पता करना आदि शामिल हैं।

शुक्र की सतह का अध्ययन करने के लिए यान में हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक एपर्चर रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। यह ग्रह के चारों ओर बादलों के बावजूद शुक्र की सतह की जांच करेगा।

इस मिशन को दिसंबर 2024 में इसलिए लॉन्च किया जा रहा है क्योंकि तब पृथ्वी और शुक्र एक सीध में आ जाएंगे। अगर इस समय लॉन्चिंग होती है तो बेहद ही कम प्रणोदक यानी प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करके यान को शुक्र की ऑर्बिट में स्थापित किया जा सकेगा। अगर दिसंबर 2024 में यह लॉन्चिंग नहीं हुई तो उस तरह की अनुकूल खगोलीय स्थिति साल 2031 में बन पाएगी।

अबतक अमेरिका, रूस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान ही शुक्र मिशन लांच कर पाए हैं और इन सारे मिशनों की संख्या लगभग 46 है। इनमें से कुछ अंतरिक्ष यान शुक्र के पास पहुंचे, कुछ उसकी कक्षा में पहुंचे। इन मिशनों को 3 तरह से बांटा जा सकता है-

1) फ्लाइबाई यानी प्लेनेट के नजदीक से स्पेसक्राफ्ट गुजरता है

2) लैंडर मिशन यानी जिसमें स्पेसक्राफ्ट से उपकरण को ग्रह की सतह पर लैंड कराया जाता है

3) ऑर्बिटर मिशन यानी जिसमें संबंधित ग्रह के ऑर्बिट यानी कक्षा में स्पेसक्राफ्ट चक्कर लगाता रहता है।

भारत का यह संभावित शुक्र मिशन आर्बिटर मिशन होगा।

शुक्र की उप-सतह (sub-surface) का अभी तक किसी भी देश द्वारा कोई अवलोकन नहीं किया गया है। सितंबर 2020 में वैज्ञानिकों ने शुक्र पर फास्फीन गैस मिलने का दावा किया था। यह गैस सूक्ष्म-जीव भी बनाते हैं। ऐसे में भारतीय मिशन पृथ्वी के बाहर जीवन की पुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

2 कार्बन कैप्चर की विद्युत रासायनिक विधि

संदर्भ :-

- लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी, कै. लिफोर्निया के प्रोफेसर ब्रायन मैकक्लोस्की कार्बन पृथक्करण के लिए संभावित रूप से सस्ता दृष्टिकोण लेकर आए हैं। उनकी विधि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए इलेक्ट्रोकैमिस्ट्री (विद्युत रसायन) का उपयोग करती है।
- वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड यानी डायरेक्ट एयर कैप्चर से कार्बन के संग्रहण का यह एक अच्छा विकल्प है, जिसे कुछ जगहों पर आजमाया जा रहा है।

विद्युत रासायनिक विधि :-

- विद्युत रसायन विधि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए इलेक्ट्रोकैमिस्ट्री का उपयोग करती है। इलेक्ट्रोकैमिस्ट्री में मोटे तौर पर इलेक्ट्रॉन देने या प्राप्त करने वाले परमाणु शामिल होते हैं। यह विज्ञान सभी बैटरियों और ईंधन कोशिकाओं का आधार है। यह प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रॉक्साइड आयनों के साथ अभिक्रिया के द्वारा बाइकार्बोनेट आयन बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रॉक्साइड आयनों को पृथक करने के लिए विद्युत रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है, जिससे गैस को पृथक कर हाइड्रॉक्साइड आयनों का पुन: उपयोग किया जा सके।
- इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, प्रत्येक

इलेक्ट्रोड पर दो अभिक्रियाएं होती हैं। एक इलेक्ट्रोड पर, कार्बन डाइऑक्साइड की एक दबावयुक्त धारा बनाने के लिए बाइका. र्बोनेट को ऑक्सीकृत किया जाता है, जिसे अनुक्रमित किया जा सकता है। जबकि दूसरे इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जो क्षारीय घोल को पुनः उत्पन्न करने के लिए प्रोटॉन की खपत करती है। इस प्रकार, अभिक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की एक धारा और एक धारा हाइड्रोजन की उत्पन्न होती है।

कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या है?

- कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक उत्पादित ग्रीनहाउस गैस है। कार्बन पृथक्करण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर और संग्रहीत करने की प्रक्रिया है। यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन को कम करने के लक्ष्य के साथ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने की एक विधि है।

कार्बन कैप्चर के प्रकार :-

- **जैविक :-**
  - o जैविक कार्बन कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड का प्राकृतिक भंडारण है। इसमें पौधों में भंडारण (स्वाभाविक रूप से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है), पेड़, मिट्टी और महासागर कार्बन अनुक्रम शामिल हैं। पौधों और पेड़ों की जड़ें कार्बन पृथक्करण में उत्कृष्ट भूमिका निभ. ाती हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में कार्बन संचित रहता है।

- **भूवैज्ञानिक :-**
  - o भूवैज्ञानिक कार्बन अनुक्रम तब होता है जब CO_2 को भूवैज्ञानिक चट्टानी संरचनाओं में संरचित किया जाता है। इस प्रकार का कार्बन कैप्चर वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में लागू किया जा रहा है। इस्पात, ऊर्जा और प्राकृतिक गैस उत्पादन जैसे उद्योग कार्बन डाइऑक्साइड को पृथ्वी में गहराई में संचित करते हैं, इसलिए यह वातावरण में नहीं फैलती। लेकिन, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (सीसीएस) के माध्यम से भूगर्भिक अनुक्रम अभी भी काफी हद तक अप्रमाणित दृष्टिकोण है।

- **प्रौद्योगिकीय :-**
  - o अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड से उपयोगी उप-उत्पाद बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का एक समूह एक ऐसी प्रक्रिया का विकास कर रहा है जो CO_2 को मीथेन और पानी में बदल देती है। मीथेन को तब बिजली या बिजली वाहनों के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्राफीन नामक पदार्थ बनाया गया है। ग्राफीन का उपयोग अभी भी सीमित है, लेकिन यह स्मार्टफोन स्क्रीन जैसे उपकरणों में उपयोग किया जाता है।

भारत और कार्बन पृथक्करण :-

- CO_2 भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम और अनुसंधान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- भारत त्वरित सीसीएस प्रौद्योगिकी (एसीटी) पहल का हिस्सा है।
- त्वरित सीसीएस प्रौद्योगिकी (एसीटी),16 देशों की एक अंतरराष्ट्रीय पहल है जिसमें लक्षित नवाचार और अनुसंधान गतिविधियों के माध्यम से सीसीयूएस प्रौद्योगिकी के विकास और उन्हें परिपक्व करने के उद्देश्य से परियोजनाओं के अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करती है।
- 2050 तक लगभग शून्य उत्सर्जन के लिए 'उद्योग चार्टर' पर छह भारतीय कंपनियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी जो कार्बन पृथक्करण सहित विभिन्न डीकार्बोनाइजेशन उपायों की खोज करेंगी।

आगे की राह :-

वैश्विक नेताओं के लिए 2050 तक शुद्ध शून्य-उत्सर्जन (जैसा कि आईपीसीसी रिपोर्ट में कहा गया है, पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ते तापमान से बचाने के लिए) प्राप्त करने का यह एक व्यवहार्य विकल्प है। समता और जलवायु न्याय के सिद्धांतों के आधार पर व्यावहारिक प्रौद्योगिकी विकास और सभी के लिए सस्ती दरों पर इस प्रौद्योगिकी की पहुंच के लिए, एक गंभीर वैश्विक सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है।

NOTES

आर्थिक

1 एमएसएमई के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने के पांच माध्यम

सन्दर्भ :-

- बड़े फर्मो के समान ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भी अपने व्यवसायों को सफलतापूर्वक संचालित करने, विकसित करने तथा बढ़ाने के लिए शक्तिशाली और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता होती है।
- बेहतर इन्वेंट्री टर्नअराउंड, व्यावसायिक संसाधनों के अनुकूलन और समग्र प्रणाली की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला महत्वपूर्ण है।
- इसके साथ ही बेहतर आपूर्ति श्रृंखला ग्राहकों को सर्वोत्तम माध्यम से सेवा प्रदान करने और उनके साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है।

भारतीय एमएसएमई में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के तरीके :-

1. प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (की-परफॉर्मेंस इंडिकेटर) निर्धारित करें :-

- प्रारंभिक चरण में उपयुक्त मुख्य प्रदर्शन संकेतक (KPI) को निर्दिष्ट करना आवश्यक है। किसी भी आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न की-परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं। इनमें लागत, इन्वेंट्री टर्नअराउंड समय, गति, ग्राहक संतुष्टि, शिकायतों की समग्र निवारण दर इत्यादि महत्वपूर्ण हैं।
- व्यवसाय और उसकी दीर्घकालिक रणनी. ति के अंतर्गत एक एमएसएमई को केपीआई को निर्दिष्ट कर उस आधार पर कार्य करना होता है।
- इस प्रक्रिया में, प्रत्येक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को एक वेटेज स्कोर देना महत्वपूर्ण है क्योंकि एक व्यवसाय के लिए एक इंडिकेटर महत्वपूर्ण हो सकता है वह दूसरे के लिए भी उतना महत्वपूर्ण हो ऐसा नहीं कहा जा सकता।

2. एक एकीकृत मंच का प्रयोग करें :-

- एक एमएसएमई में भी, कई कार्य एक साथ संचालित होते हैं। इस प्रकार एक एकीकृत प्रणाली विकसित करना महत्वपूर्ण है जो एक ही डैशबोर्ड के तहत उत्पादन, अन्य व्यावसायिक संचालन, विपणन और रसद जैसे कई व्यक्तिगत कार्यों को एकीकृत कर सके।
- एक एकीकृत प्रणाली सभी कार्यों में डेटा का एक वास्तविक समय और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करेगी जिससे व्यावसायिक नेतृत्व को एक समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- एकीकृत मंच में पारदर्शिता जितनी अधिक होगी, श्रृंखला के सभी तत्वों का सिंक्रनाइजेशन उतना ही सुगम तथा बेहतर होगा।

3. मांग के लिए भविष्यगामी विश्लेषण का प्रयोग :-

- आपूर्ति श्रृंखला दक्षता के लिए उपभोक्ता वरीयताओं का विश्लेषण तथा मांग की सटीक भविष्यवाणी करना सर्वोपरि है। यह विश्लेषण लक्षित तथा सटीक योजना बनाने में सहायता करता है।
- पिछले रुझानों की जांच करने से भविष्य के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है और निर्णय लेने में सुधार हो सकता है।
- मांग पूर्वानुमान के द्वारा कच्चे माल के साथ-साथ तैयार उत्पादों के बेहतर सूची के प्रबंधन में सहायता मिलती है ।
- इसने हमें स्टॉक-आउट और ओवरस्टॉकिंग दोनों से बचने में सक्षम बनाया है जो लागत अनुकूल होती है ।
- इसके अलावा, यह उपभोक्ता व्यवहार में हो रहे परिवर्तन का पता लगाने में सहायता करता है।

4. पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी का विकास:-

- लॉजिस्टिक संसाधनों और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं सहित विश्वसनीय भागीदारों की पहचान करना दीर्घकाल में लाभकारी सिद्ध होगा।
- सही साझेदार होने और उन्हें खुले और स्पष्ट संचार में शामिल करने से व्यवसाय की अनिश्चितता कम हो सकती है और किसी की आपूर्ति श्रृंखला को कई गुना मजबूत किया जा सकता है।
- भागीदारों के साथ व्यवहार करते समय, उनकी चिंताओं को भी समझना महत्वपूर्ण है, जिससे पारस्परिक रूप से लाभप्रद और स्थायी संबंध बनाया जा सके।

5. मानव संसाधन चुनौती का समाधान :-

- एक विशेष आपूर्ति श्रृंखला टीम का होना हमेशा विवेकपूर्ण होता है भले ही श्रृंखला कितनी भी छोटी क्यों न हो।
- यह न केवल परिचालन अनुकूलता में मदद करेगा, बल्कि आने वाले समय में व्यवसाय को बढ़ाने में भी सहायक होगा।
- एक समर्पित टीम होने से संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर उपभोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिली है।
- इसने विनिर्माण को सुव्यवस्थित करने में भी मदद की है।

निष्कर्ष :-

ऐसे समय में आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब छोटे अथवा बड़े आकार की फर्म कोविड प्रेरित व्यवधानों से ग्रस्त हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में, निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने और मिश्रित जोखिमों को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

2 क्रिप्टो और सीबीडीसी के बीच अंतर

खबरों में क्यों?

हाल ही में, RBI ने घोषणा की है कि वह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) लॉन्च करने की योजना बना रहा है।

क्रिप्टोकरेंसी क्या है?

क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है जिसे क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित किया जाता है कई क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित और विकेंद्रीकृत नेटवर्क हैं। क्रिप्टो. करेंसी की एक परिभाषित विशेषता यह है कि वे आम तौर पर किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं की जाती हैं, जो उन्हें सैद्धांतिक रूप से सरकारी हस्तक्षेप या हेरफेर से प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) क्या है?

केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राएं एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी क्रिप्टोकरेंसी के समान डिजि. टल टोकन हैं। वे उस देश की फिएट मुद्रा के मूल्य से आंकी जाती हैं, जिससे सरकारी हस्तक्षेप की गुंजाइश बच जाती है।

क्रिप्टो और सीबीडीसी में क्या अंतर है?

केंद्रीय बैंक को ध्यान देना चाहिए कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) केवल एक फिएट करेंसी हो सकती है और क्रिप्टो नहीं, क्योंकि CBDC राज्य के समर्थन के साथ एक्सचेंज के टोकन के रूप में कार्य करेगा इसलिए यह क्रिप्टो के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

क्रिप्टो एक कंप्यूटर प्रोग्राम में संख्याओं की एक स्ट्रिंग है, जिसमें कोई राज्य समर्थन नहीं है लेकिन अच्छी तरह से उनकी स्वीकार्यता उन्हें पैसे के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती है। तो, क्रिप्टो मूल्य प्राप्त करते हैं और नेट के माध्यम से लेनदेन किया जा सकता है। यह उन्हें पैसे के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है।

क्रिप्टो में अंतर्निहित कठिनाइयों की विभिन्न डिग्री 'दोहरे खर्च' की समस्या से संबंधित हैं। फिएट करेंसी में ऐसी खूबी होती है जिसे एक बार खर्च कर देने के बाद उससे फिरसे खर्च नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह खर्च करने वाले के पास नहीं है। लेकिन कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर को बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है।

ब्लॉकचेन विकेंद्रीकरण को सक्षम बनाता है। यानी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर सभी अपनी बात रख सकते है। लेकिन, केंद्रीय बैंक ऐसा नहीं चाहेंगे। वे चाहते हैं कि सीबीडीसी जैसी फिएट मुद्रा विशेष रूप से उनके द्वारा जारी और नियंत्रित की जाए। लेकिन, सैद्धांतिक रूप से हर कोई श्माइनश कर सकता है और क्रिप्टो बना सकता है। इसलिए, सीबीडीसी वास्तव में विकेन्द्रीकृत डिजिटल संपत्ति नहीं है।

अत: सीबीडीसी वर्तमान में क्रिप्टो के लिए एक विकल्प नहीं हो सकता है जो जल्द ही पैसे के रूप में उपयोग करना शुरू कर देगा। इसका असर केंद्रीय बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के कामकाज पर पड़ेगा।

आगे की राह

एक केंद्रीकृत सीबीडीसी को प्रत्येक लेनदेन को सत्यापित करने के लिए RBI की आवश्यकता होगी, कुछ ऐसा जो वर्तमान में RBI नहीं कर रहा है। एक बार करेंसी नोट जारी होने के बाद RBI लेनदेन में इसके उपयोग पर नजर नहीं रखता है। ट्रैक रखना बहुत जटिल होगा जो CBDC जैसे क्रिप्टो को अनुपयोगी बना सकता है जब तक कि नए सुरक्षित प्रोटोकॉल तैयार नहीं किए जाते।

सीबीडीसी वर्तमान में क्रिप्टो के लिए एक विकल्प नहीं हो सकता है, जिसे जल्द ही पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जाना शुरू हो जाएगा। इसका असर केंद्रीय बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के कामकाज पर पड़ेगा। इसके अलावा, क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाने के लिए वैश्विक समन्वय की आवश्यकता होती है, जिसकी संभावना कम ही लगती है। अंत. र्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टा. लिना जॉर्जीवा ने कहा है, "पैसे का इतिहास एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है"।

NOTES

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें

1. इसरो नेत्रा परियोजना की सहायता से अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करेगा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) नए रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप अंतरिक्ष पिंड अनुवर्तन एवं विश्लेषण नेटवर्क (नेत्रा) की मदद से अंतरिक्ष मलबा ट्रैकिंग क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है। इस परियोजना के तहत 1,500 किमी की रेंज वाला स्पेस मलबा ट्रैकिंग रडार और एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित किया जाएगा। रडार की विशेषता यह है कि यह 10 सेमी से अधिक आकार की वस्तुओं का पता लगा सकने में सक्षम है। इस रडार को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है। इसरो 1000 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे दो राडार तैनात करेगा। वर्ष 2021 में इसरो ने करीब 3,148 घटनाओं की निगरानी की जब भूस्थैतिक कक्षा में अन्य वस्तुओं और भारतीय उपग्रहों के बीच की दूरी 5 किमी से कम थी। भारतीय उपग्रहों को जिन वस्तुओं से खतरा हो सकता था, उनमें अधिकतम संख्या चीन के उपग्रह फेंग्युन-1C और कोसमॉस-इरिडियम उपग्रहों के टुकड़े हैं। बता दें कि अंतरिक्ष मलबा अंतरिक्ष वस्तुओं के टुकड़े, मृत उपग्रह के टुकड़े होते हैं, जो 27,000 किमी प्रति घंटे की औसत गति से घूमते हैं।

2. उत्तर प्रदेश सरकार ने 'स्कूल चलो अभियान' शुरू किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 100% नामांकन के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुवात की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती जिले से अभियान की शुरुआत की। बता दें कि यह उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे निरक्षर जिलों में से एक है। अभियान के तहत छात्रों को यूनिफार्म और जूते-मोजे उपलब्ध कराए जाएंगे। 'स्कूल चलो अभियान' से जनप्रतिनिधि को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विधायक से एक स्कूल गोद लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों को नया रूप दिया है।

उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर :-

उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर% 79.24 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 59.26 प्रतिशत है। जबकि उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर 69.72% है। उच्चतम साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर जिले में दर्ज की गई है जबकि सबसे कम श्रावस्ती जिले में है।

3. वित्त वर्ष 2022 और 2023 में भारत की जीडीपी क्रमशः 7.5% और 8% की दर से बढ़ेगी

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने एशियाई विकास आउटलुक (एडीओ) 2022 में अनुमान लगाया है कि 2022 में भारत की जीडीपी 7.5% और 2023 में 8% की दर से बढ़ेगी। वहीं एडीबी ने बताया कि दक्षिण एशिया में (2022 में) विकास दर घटकर 7% रहेगी और 2023 में बढ़कर 7.4% हो जाएगी। रिपोर्ट में एशिया की जीडीपी पर भी अनुमान लगते हुए बताया गया है कि एशिया की अर्थव्यवस्था 2022 में 5.2% और 2023 में 5.3% की दर से बढ़ेगी।

एशियाई विकास आउटलुक (एडीओ) :-

सालाना मार्च/अप्रैल में प्रकाशित होने वाली यह रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट एशिया के अधिकांश देशों को कवर करती है। एडीओ के लिए एक अपडेट सितंबर में प्रकाशित किया जाता है। जबकि एडीओ के संक्षिप्त ब्रीफ सप्लीमेंट्स जुलाई और दिसंबर में प्रकाशित किए जाते हैं। वहीं अन्तराष्ट्रीय परिदृश्य का आंकलन विश्व बैंक समूह द्वारा "ग्लोबल इकनोमिक प्रॉस्पेक्ट्स" और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा "विश्व आर्थिक आउटलुक" जैसी रिपोर्टों से किया जाता है।

4. भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के मध्य अभ्यास वरुण संपन्न

भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच 'वरुण' द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20 वां संस्करण 30 मार्च से 3 अप्रैल तक अरब सागर में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में दोनों नवसेनाओं की ओर से जहाज, पनडुब्बी, समुद्री गश्ती विमान, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया। बता दें कि दोनों देशों के बीच 1993 में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास शुरू किया था। आगे 2001 में अभ्यास का नाम बदलकर 'वरुण' कर दिया गया और तब से यह भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।

5. भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 43.41% की वृद्धि

अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125.62 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। जो पहले से 43.41% अधिक है। इस क्रम में भारत से चीन को निर्यात में 34.28% की वृद्धि हुई है। जो मूल्य की दृष्टि से 28.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। जबकि चीन से भारत का आयात 46.14 फीसदी बढ़कर 97.59 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा 51.53% बढ़ा है। भारत 2021 में चीन का 14वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। भारत मुख्य रूप से चीन को लौह अयस्क, हीरे, एल्यूमीनियम और परिष्कृत तांबे के कैथोड का निर्यात करता है। भारत चीन का दूसरा सबसे बड़ा हीरा निर्यातक था। चीन से भारत में विद्युत मशीनरी और उपकरणों के निर्यात में 36.77 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। भारत 2021 में चीनी कार्बनिक रसायनों के लिए सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था।

6. आईओएनएस समुद्री अभ्यास (आईएमईएक्स) 2022 संपन्न

हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) समुद्री अभ्यास (आईएमईएक्स) का पहला संस्करण 26 से 30 मार्च 22 तक अरब सागर में आयोजित किया गया। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) संचालन में पारस्परिकता को बढ़ाना है। 25 सदस्यी आईओएनएस में से 15 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। इस अभ्यास में बांग्लादेश, फ्रांस, भारत और ईरान की नौसेनाओं के युद्धपोतों, विमानों और हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया है। यह अभ्यास सदस्य देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से सामूहिक रूप से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। बता दें कि आईएमईएक्स-22 का बंदरगाह चरण गोवा के मोरमुगाओ बंदरगाह पर आयोजित किया गया।

संक्षेप में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) :-

इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। यह क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग में सुधार करने के लिए एक फोरम है। इसके सदस्य देश निम्नलिखित हैं :-

बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, सेशेल्स, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र), ईरान, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस (रीयूनियन), केन्या, मॉरीशस, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्याँमार, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर-लेस्ते।

7. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की आबादी में वृद्धि

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में नई जनगणना के अनुसार एक सींग वाले गैंडों की आबादी 2,613 तक पहुंच गई है। जबकि पिछली जनगणना में गैंडों की आबादी 2,413 दर्ज की गई थी। नवीनतम आंकड़ों में 750 वयस्क नर गैंडे और 903 वयस्क मादाएं हैं। जनगणना में 279 किशोर (1 से 3 वर्ष) और 146 बछड़े (0 से 1) भी दर्ज किए गए। वर्तमान में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडो का घनत्व प्रति 0.2 वर्ग किलोमीटर है। इस बार की गणना में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ओरंग नेशनल पार्क और पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में भी गैंडों की आबादी बढ़ी है। बता दें कि एक सींग वाले गैंडे को आईयूसीएन लाल सूची में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

संक्षेप में जाने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को :-

यह असम में ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ग्रस्त मैदानों में स्थित है। यहां एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी है। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था।

8. भारतीय हिमालयी क्षेत्र में दो भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की गई

भारतीय हिमालयी क्षेत्र में शिवालिक जीवाश्म पार्क और स्ट्रोमेटोलाइट युक्त डोलोमाइट/बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर को भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों के रूप में पहचाना गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) बेहतर सुरक्षा और रखरखाव के लिए भू-विरासत स्थलों/राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की घोषणा करता है। भूवैज्ञानिक विरासत स्थल वे स्थान हैं जहां भूगर्भिक विशेषताओं या परिदृश्यों ने सांस्कृतिक या ऐतिहासिक घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में कुल 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं।

शिवालिक जीवाश्म पार्क :-

यह हिमाचल प्रदेश के सिरमुर जिले में स्थित है। इसमें ऊपरी और मध्य शिवालिक क्षेत्रों से पाए गए प्रागैतिहासिक कशेरुकी जीवाश्मों और कंकालों का संग्रह है। यह एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क है। इसकी स्थापना 1974 में हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा की गई थी।

स्ट्रोमेटोलाइट युक्त डोलोमाइट/बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर :-

यह स्थल दक्षिण सिक्किम जिले में ममले के पास स्थित है। यह स्थल सिक्किम हिमालय में प्रारंभिक जीवन के दुर्लभ उदाहरणों में से एक है। ममले में भू-विरासत साइट प्रोटेरोजोइक युग के बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर को उजागर करती है।

9. अदालत के आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर प्रणाली की शुरुवात की गयी

अदालत के आदेशों के तेज और सुरक्षित प्रसारण के लिए FASTER (फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स) सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अब फास्टर प्रणाली की मदद से अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्थगन आदेश, जमानत आदेश आदि की सूचना दे सकते हैं। सभी नोडल अधिकारियों को एक विशिष्ट न्यायिक संचार नेटवर्क (जेसीएन) के माध्यम से जोड़ा गया है। इस प्रणाली कि मदद से अदालतें जेलों में ड्यूटी अधिकारियों को सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से जमानत आदेश, स्थगन आदेश, अंतरिम आदेश और कार्यवाही की ई-प्रमाणित प्रतियां भेज सकती हैं। इस प्रणाली का विकास रजिस्ट्री द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से किया गया है। व्यवस्था की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक फास्टर सेल भी स्थापित किया गया है। फास्टर सेल नोडल अधिकारियों को जमानत से संबंधित कार्यवाही या आदेशों के डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड को प्रसारित करेगा।

10. भारत की फाल्गुनी शाह और रिकी केज को ग्रैमी अवॉर्ड मिला

दो भारतीय संगीतकार रिकी केज और फाल्गुनी शाह 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों के विजेताओं में शामिल है। केज ने बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में एल्बम "डिवाइन टाइड्स" के लिए अपना दूसरा ग्रैमी अवार्ड जीता। इससे पहले केज को 2015 में "विंड्स ऑफ समसारा" के लिए अपना पहला ग्रैमी मिला था। वहीं फाल्गुनी शाह को एल्बम "ए कलरफुल वर्ल्ड" के लिए सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत उद्योग में उपलब्धि को मान्यता देने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार है। 64वें ग्रैमी अवॉर्ड्स के अन्य विजेता निम्नलिखित हैं :-

- एल्बम ऑफ द ईयर: जॉन बैटिस्ट द्वारा 'वी आर'
- रिकॉर्ड ऑफ द ईयर: ब्रूनो मार्स और एंडरसन पाक द्वारा "लीव द डोर ओपन"
- सॉन्ग ऑफ द इयर: "लीव द डोर ओपन," सिल्क सोनिक (ब्रेंडन एंडरसन, क्रिस्टोफर ब्रॉडी ब्राउन, डर्नस्ट एमिल II और ब्रूनो मार्स)
- बेस्ट म्यूजिक वीडियो: जॉन बैटिस्ट द्वारा "फ्रीडम"
- बेस्ट म्यूजिक फिल्म: "समर ऑफ सोल"
- बेस्ट आर एंड बी एल्बम: "हेक्स टेल्स," जैजमीन सुलिवन
- बेस्ट कंट्री सॉन्ग: क्रिस स्टेपलटन द्वारा "कोल्ड"

11. आंध्र प्रदेश फल उत्पादन में शीर्ष पर

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में आंध्र प्रदेश फल उत्पादन में एक बार फिर शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान है। उत्तर प्रदेश ने 2021-22 में दो साल के बाद शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य के रूप में अपना स्थान फिर से हासिल कर लिया है। सब्जी उत्पादक राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र का स्थान है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में भारत का कुल बागवानी उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 0.4% घटा है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कुल उत्पादन 333.25 मिलियन टन हो सकता है। बता दें कि सरकार ने बागवानी उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में "बागवानी एकीकृत विकास मिशन" की शुरुवात की थी।

शीर्ष पांच फल उत्पादक राज्य (2021-22)	शीर्ष पांच सब्जी उत्पादक राज्य (2021-22)
आंध्र प्रदेश	उत्तर प्रदेश
महाराष्ट्र	पश्चिम बंगाल
उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश
कर्नाटक	बिहार
गुजरात	महाराष्ट्र

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

- महाराष्ट्र का चंद्रपुर में दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया है।
  चर्चा में क्यों रहा है चंद्रपुर :- 29 मार्च 2022 को चंद्रपुर जिले में पहली बार जंगल की आग दर्ज की गई थी। आग इरई बांध के क्षेत्र में दर्ज की गई थी। इरई बांध महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के पास इरई नदी पर स्थित है। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।

- महेश वर्मा को अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
  एनएबीएच संक्षेप में :- इसे स्वास्थ्य सेवा संगठनों के लिए मान्यता कार्यक्रम की स्थापना और संचालन के लिए स्थापित किया गया था। यह भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक संघटक बोर्ड है।

- मुंबई की पत्रकार आरेफा जौहरी को वर्ष 2021 के चमेली देवी जैन पुरस्कार के लिय्व चुना गया है।
  चमेली देवी जैन संक्षेप में :-1982 में स्थापित यह पुरस्कार स्वतंत्रता सेनानी और समुदाय सुधारक चमेली देवी जैन की स्मृति में दिया जाता है। यह भारतीय महिला मीडियाकर्मियों को दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है, जिन्होंने सामाजिक विकास, राजनीति, समानता, लैंगिक न्याय, स्वास्थ्य, युद्ध और संघर्ष, और उपभोक्ता मूल्यों जैसे विषयों की रिपोर्टिंग की है।

- चीन में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज 'यांग्त्जी रिवर थ्री गोरजेस 1' लॉन्च किया गया। यह 100 मीटर लंबा, 16.3 मीटर चौड़ा है और इसमें 1,300 यात्रियों के बैठने की जगह है। एक बार चार्ज करने के बाद यह 100 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है।

- खगोलविदों ने पृथ्वी से 17,000 प्रकाश वर्ष दूर एक एक्सोप्लैनेट (बहिर्ग्रह) खोजा है, जो लगभग बृहस्पति के समान है। इस एक्सोप्लैनेट को **K**2-2016-**BLG**-0005**Lb** नाम दिया गया है। खगोलविदों ने बृहस्पति के समान ग्रह की खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत और गुरुत्वाकर्षण माइक्रोलेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, साथ ही ग्रह की खोज में खगोलविदों ने नासा के केपलर सैटेलाइट टेलीस्कोप से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग भी किया है।

- भारत-किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास "खंजर" का 9वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में संपन्न हुआ।

- प्रोफेसर रामदरश मिश्र को उन्हें उनके कविता संग्रह 'मैं तो यहां हूं' के लिए 2021 का सरस्वती सम्मान दिया जायेगा।
  सरस्वती सम्मान संक्षेप में :- के.के. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में की गयी थी। यह भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी एक में गद्य या कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह सम्मान पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित कार्य के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था।

- फोर्ब्स की अमीरों की 2022 की सूची में स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत के मुकेश अंबानी इस सूची में दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नादर, साइरस पूनावाला और राधाकिशन दमानी फोर्ब्स की 36वीं अमीरों की सूची में शीर्ष 5 भारतीय हैं। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची 2022 में सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला हैं। जबकि इस साल की सूची में फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स को इस साल दुनिया की सबसे अमीर महिला के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

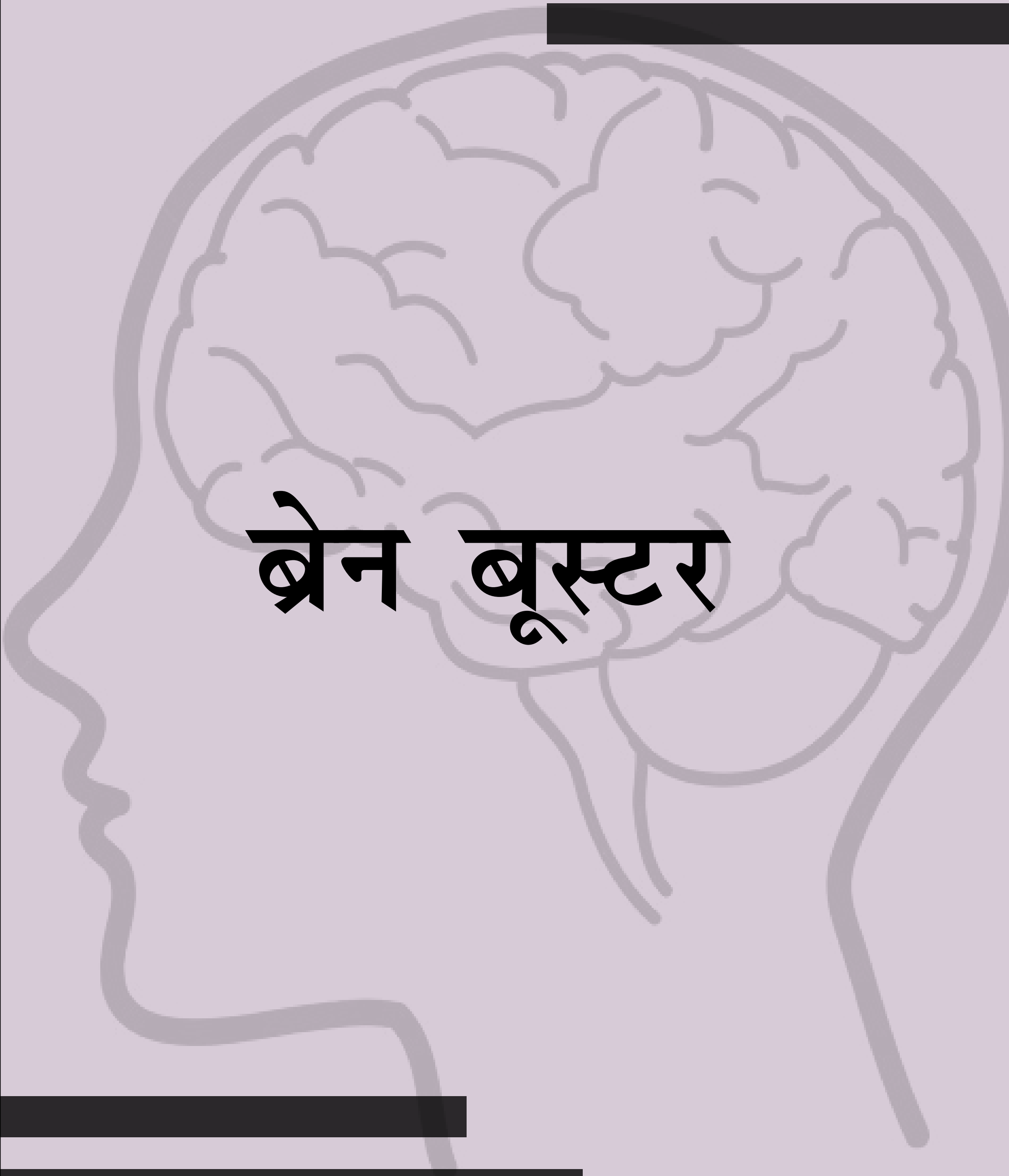

ब्रेन बूस्टर

प्रतिकूल अधिग्रहण के खिलाफ रक्षा तंत्र

1. खबरों में क्यों

एलोन मस्क ने ट्विटर को लगभग 44 बिलियन डॉलर में खरीदने का समझौता किया। यह बिक्री, बोर्ड के लिए एक नाटकीय बदलाव था क्यूंकि बोर्ड ने मूल रूप से मिस्टर मस्क को ट्विटर खरीदने में बाधा उत्पन्न की थी।

2. प्रतिकूल अधिग्रहण के बारे में

एक शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण एक प्रकार का अधिग्रहण है जिसमें एक बोलीदाता, लक्ष्य के प्रबंधन या निदेशक मंडल की सहमति के बिना और इच्छा के विरुद्ध लक्ष्य कंपनी का अधिग्रहण करता है। एक बोलीदाता द्वारा लक्षित कंपनी में एक निर्धारित शेयर खरीदने के बाद प्रतिकूल अधिग्रहण निष्पादित किए जाते हैं

3. रक्षा तंत्र के बारे में

- यह विलय और अधिग्रहण लेनदेन में, प्रक्रियाओं का सेट है जो एक लक्षित कंपनी द्वारा प्रतिकूल अधिग्रहण को रोकने के लिए नियोजित किया जाता है।
- आम तौर पर, रक्षा तंत्र को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:
  - प्री-ऑफर रक्षा तंत्र
  - प्रस्ताव के बाद रक्षा तंत्र

4. प्री-ऑफर रक्षा तंत्र के प्रकार

प्री-ऑफर डिफेंस एक प्री-एमपटिव रणनीति है। प्री-ऑफर रक्षा तंत्र में निम्नलिखित रणनीतियाँ शामिल हैं:

- **पोइजन पिल**

पोइजन पिल की नीति में लक्ष्य कंपनी के शेयरों को कमजोर करना शामिल है ताकि संभावित अधिग्रहणकर्ता के लिए लक्षित कंपनी में नियंत्रित हित प्राप्त करना अधिक कठिन और महंगा हो जाये।

- **पोइजन पुट**

पोइजन पुट की रणनीति में लक्षित कंपनी द्वारा बांड जारी करना शामिल है जिसे कंपनी के प्रतिकूल अधिग्रहण की स्थिति में उनकी परिपक्वता तिथि से पहले भुनाया जा सकता है।

- **गोल्डन पैराशूट**

गोल्डन पैराशूट का तात्पर्य कंपनी के शीर्ष प्रबंधन कर्मचारियों को उनके रोजगार की समाप्ति के मामले में लाभ, बोनस या विच्छेद वेतन से है।

- **सुपरमेजॉरिटी प्रावधान**

एक सुपरमेजॉरिटी प्रावधान कॉर्पोरेट चार्टर में एक संशोधन है। इसके अंतर्गत कंपनी के विलय या अधिग्रहण को बोर्ड द्वारा तभी अनुमोदित किया जा सकता है, यदि शेयरधारकों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत (आमतौर पर 70% से 90%) विलय या अधिग्रहण के पक्ष में मतदान करे।

5. पोस्ट-ऑफर रक्षा तंत्र के प्रकार

जब एक लक्षित कंपनी प्रतिकूल अधिग्रहण के लिए बोली प्राप्त करती है, तब पोस्ट-ऑफर रक्षा तंत्र उपयोग में लाये जाते हैं । पोस्ट-ऑफर रक्षा तंत्र के उदाहरण हैं:

- **ग्रीनमेल डिफेंस**

ग्रीनमेल डिफेंस से तात्पर्य लक्षित कंपनी से है जो एक अधिग्रहण बोलीदाता से अपने स्वयं के स्टॉक के शेयर वापस खरीदता है। बोलीदाता कंपनी ने प्रतिकूल अधिग्रहण से पहले ही पर्याप्त संख्या में लक्षित कंपनी के शेयर खरीद लिए होते हैं। "ग्रीनमेल" शब्द "ग्रीनबैक" डॉलर और "ब्लैकमेल" से लिया गया है।

- **क्राउन ज्वेल डिफेंस**

क्राउन ज्वेल डिफेंस रणनीति में लक्षित कंपनी की सबसे मूल्यवान संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को बेचना या संपत्ति को एक अलग इकाई में बदलना शामिल है। क्राउन ज्वेल रक्षा रणनीति का मुख्य लक्ष्य लक्षित कंपनी को कॉर्पोरेट रेडर के लिए कम आकर्षक बनाना है।

- Pac-Man **डिफेंस**

Pac-Man डिफेंस तब होती है जब एक लक्षित कंपनी अपने संभावित अधिग्रहणकर्ता को हासिल करने का प्रयास करती है तथा संभावित अधिग्रहणकर्ता से अधिग्रहण बोली पहले ही प्राप्त हो चुकी होती है। जिस प्रकार अधिग्रहणकर्ता लक्षित कंपनी में निर्धारित शेयर खरीदने का प्रयास कर रहा है, वैसे ही लक्षित कंपनी, अधिग्रहणकर्ता कंपनी में एक निर्धारित शेयर खरीदने का प्रयास करता है।

- **व्हाइट नाइट डिफेंस**

व्हाइट नाइट डिफेंस एक रणनीति है जिसमें अपने रणनीतिक साझेदार द्वारा एक लक्षित कंपनी का अधिग्रहण किया जाता है। इसे व्हाइट नाइट कहा जाता है, क्योंकि यह लक्षित कंपनी के अनुकूल है।

हाइड्रोजन

हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस का एक स्वच्छ विकल्प है। यह ब्रहमांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है, जो ब्रह्मांड के द्रव्यमान में 75% योगदान करने का अनुमान है। पृथ्वी पर, पानी, पौधों और जानवरों में बड़ी संख्या में हाइड्रोजन परमाणु निहित हैं। यह जीवित चीजों में लगभग सभी अणुओं में मौजूद होता है, परन्तु यह गैस के रूप में बहुत दुर्लभ है ।

1. भविष्य के स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन का महत्व

- ईंधन एक रसायन है जिसे उपयोगी ऊर्जा प्रदान करने के लिए 'जलाया' जा सकता है।
- सामान्य रूप से जलने का अर्थ है कि ईंधन में तत्वों के बीच रासायनिक बंधन टूट जाते हैं और तत्व रासायनिक रूप से ऑक्सीजन (अक्सर हवा से) के साथ जुड़ जाते हैं।
- जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं, तो एकमात्र अपशिष्ट उत्पाद जल वाष्प होता है।

2. हाइड्रोजन का उत्पादन

- हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए, इसे जहां यह होता है, अणुओं के अन्य तत्वों से अलग किया जाना चाहिए ।
- हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए दो सबसे सामान्य तरीके स्टीम-मीथेन रेफोर्मिंग और इलेक्ट्रोलिसिस हैं।

3. उत्पादन के अनुसार हाइड्रोजन का वर्गीकरण

A. हरित हाइड्रोजन

- हरित हाइड्रोजन वह है जो बिना किसी हानिकारक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के उत्पन्न होती है।
- हरित हाइड्रोजन अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, जैसे सौर या पवन ऊर्जा, से पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए स्वच्छ बिजली का उपयोग करके बनाया जाता है।

B. ब्लू हाइड्रोजन

- ब्लू हाइड्रोजन मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस से. उत्पन्न होती है, जिसे स्टीम रिफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जाता है।
- उत्पादन हाइड्रोजन है – लेकिन उप-उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड भी है ।
- इस कार्बन को ट्रैप और स्टोर करने के लिए कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (CCS) आवश्यक है।
- नीले हाइड्रोजन को 'निम्न कार्बन हाइड्रोजन' भी कहा जाता है।

C. ग्रे हाइड्रोजन

- वर्तमान में, यह हाइड्रोजन उत्पादन का सबसे सामान्य रूप है।
- ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस, या मीथेन से स्टीम मीथेन रिफोरमेंशन का उपयोग करके बनाया जाता है, लेकिन प्रक्रिया में बने ग्रीनहाउस गैसों को कैप्चर नहीं किया जाता ।

D. काला और भूरा हाइड्रोजन

- इसमें हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया में काले कोयले या लिग्नाइट (भूरा कोयला) का उपयोग किया जाता है। यह पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है।

E. गुलाबी हाइड्रोजन

- गुलाबी हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रो. लिसिस के माध्यम से उत्पन्न होता है।

F. फिरोजी हाइड्रोजन

- फिरोजी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ठोस कार्बन का उत्पादन करने के लिए मीथेन पायरोलिसिस नामक प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जाता है।

G. पीला हाइड्रोजन

- पीला हाइड्रोजन सौर ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलि. सिस के माध्यम से बने हाइड्रोजन के लिए एक अपेक्षाकृत नया वाक्यांश है।

H. सफेद हाइड्रोजन

- सफेद हाइड्रोजन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला भूगर्भीय हाइड्रोजन है जो भूमिगत निक्षेपों में पाया जाता है और फ्रैकिंग द्वारा निर्मित होता है।
- वर्तमान में इस हाइड्रोजन के दोहन की कोई विधि नहीं है।

4. क्या हाइड्रोजन का पहले से ही ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है?

- ऐसी कारें हैं जो हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चलती हैं।
- जापान में 96 सार्वजनिक हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन हैं।
- जर्मनी में 80 हाइड्रोजन स्टेशन हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका 42 स्टेशनों के साथ तीसरे स्थान पर है।

5. हाइड्रोजन अपनाने में रुकावटें

- हाइड्रोजन को मीथेन का एक व्यवहार्य विकल्प बनाने के लिए, इसे बड़े पैमाने पर, आर्थिक रूप से उत्पादित किया जाना चाहिए और वर्तमान बुनियादी ढांचे को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

6. भारत की योजना

- बिजली मंत्रालय के अनुसार, भारत की योजना 2030 तक प्रति वर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का निर्माण करने की है।
- भारत अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और ईंधन के लिए उत्पादन और निर्यात केंद्र बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।

भारत में हीट वेव की एक असामान्य रूप से लंबी श्रृंखला देखी जा रही है जो मार्च के अंत में शुरू हुई और अधिकांश अप्रैल में उत्तर भारत को झुलसा दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 122 वर्षों में उत्तर पश्चिम भारत में अप्रैल सबसे गर्म रहा। अप्रैल में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर छूने के साथ-साथ असामान्य रूप से गर्म भी रहा है।

हीट वेव

1. हीटवेव के बारे में

- अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री अधिक होने पर हीटवेव की घोषणा की जाती है।
- आईएमडी के अनुसार, यदि सामान्य तापमान से 6.4 डिग्री अधिक है, तो भीषण हीटवेव की घोषणा की जाती है।
- पूर्ण रिकॉर्ड किए गए तापमान के आधार पर, एक हीटवेव तब घोषित की जाती है जब कोई क्षेत्र का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।
- अधिकतम तापमान 47 डिग्री को पार कर जाने पर भीषण हीटवेव की घोषणा की जाती है।

2. भारत में हीटवेव का प्रसार

- आईएमडी के रिकॉर्ड बताते हैं कि 27 अप्रैल तक औसत अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस था, जो इस महीने के लिए पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है।
- मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में अप्रैल 2022 में अब तक का औसत अधिकतम तापमान, 1951 के बाद सबसे अधिक रहा है।
- औसत अधिकतम तापमान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दूसरे स्थान पर रहा है।
- इनमें से अधिकांश राज्यों में, वर्ष के इस समय के लिए तापमान लगातार 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और सामान्य से लगभग 5-6 डिग्री अधिक रहा है।

- आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी।
- हिमाचल प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी यह असामान्य रूप से गर्म है।

3. पोस्ट-ऑफर रक्षा तंत्र के प्रकार

- एक क्षेत्र में गर्म शुष्क हवा का प्रसार: गर्म शुष्क हवा का एक क्षेत्र और क्षेत्र में गर्म हवा के परिवहन के लिए उपयुक्त प्रवाह पैटर्न होना चाहिए।
- ऊपरी वायुमंडल में नमी की अनुपस्थिति: नमी की उपस्थिति तापमान वृद्धि को प्रतिबंधित करती है।
- आकाश का बादल रहित होना क्षेत्र में अधिकतम इन्सुलेशन की स्थिति के लिए।

- क्षेत्र में बड़े आयाम वाले एंटी-साइक्लोनिक प्रवाह।
- हीट वेव आम तौर पर उत्तर पश्चिम भारत में विकसित होती हैं और धीरे-धीरे पूर्व और दक्षिण की ओर फैलती हैं लेकिन पश्चिम की ओर नहीं (चूंकि इस मौसम के दौरान हवाएं सामान्यतः पश्चिम से उत्तर-पश्चिम की ओर होती हैं)।
- लेकिन कुछ अवसरों पर, अनुकूल परिस्थितियों में किसी भी क्षेत्र में हीट वेव भी विकसित हो सकती है।

4. जलवायु परिवर्तन की भूमिका

- ग्लोबल वार्मिंग के हीट-ट्रैपिंग परिणामों का अर्थ है कि जलवायु चरम जैसे हीटवेव्स की आवृत्ति में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- देश के उत्तरी भागों में भीषण गर्मी का मुख्य कारण वर्षा की कमी है।
- वर्षा वाले पश्चिमी विक्षोभ विश्व के सबसे उत्तरी भागों और पश्चिम एशिया से गुजरने वाले अक्षांशों के बीच तापमान प्रवणता के कारण उत्पन्न होते हैं।
- कमजोर प्रवणता का अर्थ कमजोर बारिश है।
- इस मार्च और अप्रैल में, प्रशांत महासागर में सामान्य से अधिक ठंडी स्थिति उत्तर भारत में वर्षा में सहायता करने में विफल रही।

5. भारत पर हीटवेव का प्रभाव

- वर्षों शोध से पता चलता है कि भारत में हीटवेव दिनों की संख्या हर दशक में बढ़ रही है।
- 1981-90 में 413 दिन से 2001-10 में 575 दिन और 2011-20 में 600 दिन , 103 मौसम स्टेशनों पर अत्यधिक गर्म दिन दिखने वाले दिनों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
- आईएमडी के वैज्ञानिकों के एक शोध अध्ययन के अनुसार, भारत में पिछले 50 वर्षों में हीटवेव ने 17,000 से अधिक लोगों की जान ली है।

- हालांकि, हीटवेव की तीव्रता और लंबाई का भारत के मानसून से कोई सीधा संबंध नहीं है जो जून में केरल से भारत में प्रवेश करता है।

आरबीआई ने दरें बढ़ाई

भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई को अचानक कदम उठाते हुए, मुद्रास्फीति का हवाला देते हुए रेपो दर को 40 आधार अंक (इचे), 4% से बढ़ाकर 4.4% कर दिया, जो विश्व स्तर पर "खतरनाक रूप से बढ़ रही और तेजी से फैल रही है। रेपो रेट में बढ़ोतरी अगस्त 2018 के बाद पहली बार हुई है।

1. महत्वपूर्ण दरें

- **रेपो दरः** रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है।
- **रिवर्स रेपो दरः** रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है।
- **बैंक दरः** बैंक दर वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा वसूल की जाने वाली दर है।
- **नकद आरक्षित अनुपातः** नकद आरक्षित अनुपात ग्राहकों की कुल जमा राशि का एक निर्दिष्ट न्यूनतम अंश है, जिसे वाणिज्यिक बैंकों को या तो नकद में या केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में भंडार के रूप में रखना होता है।
- **मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी :** मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF), अंतर-बैंक तरलता पूरी तरह समाप्त होने की दशा में, भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने के लिए, बैंकों के लिए आपातकालीन व्यस्था है।

2. पिछले दो साल से बढ़ रही महंगाई

- कानून के अनुसार, आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति को 4% पर लक्षित करना चाहिए।
- हालांकि, कानून में आरबीआई को कुछ छूट दी गई है; यह खुदरा मुद्रास्फीति को किसी भी तरफ 2 प्रतिशत अंक से भिन्न करने की अनुमति देता है।
- इसलिए, किसी विशेष महीने में, आरबीआई मुद्रास्फी. ति को 2% या 6% होने की अनुमति दे सकता है।

- हालांकि, कुल मिलाकर, मुद्रास्फीति लगभग 4% होनी चाहिए । 2% से 6% की छूट का मतलब यह नहीं है कि आरबीआई मुद्रास्फीति को सभी या अधिकतर समय 6% पर रहने की अनुमति दे सकता है।
- अक्टूबर 2019 से अब तक सिर्फ एक महीना में ही खुदरा महंगाई दर 4% के करीब रही है।
- 2020 में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन सहित अन्य सभी महीनों में, मुद्रास्फीति 4% से अधिक थी, और अक्सर 6% से भी अधिक थी।

3. वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

- अपने बयान में, आरबीआई ने यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों को भारत में उच्च मुद्रास्फीति के प्रमुख कारणों में से एक बताया।
- लेकिन कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बारे में आरबीआई को फरवरी में भी पता था।

4. उच्च कोर मुद्रास्फीति के बारे में

- आरबीआई ने कहा है कि "आने वाले महीनों में कोर मुद्रास्फीति के ऊंचे रहने की संभावना है।"
- कोर मुद्रास्फीति का बढ़ना अक्सर अधिक चिंताजनक होता है क्योंकि इसमें वृद्धि और गिरावट दोनों में अधिक समय लगता है।
- खाद्य और ईंधन की कीमतों में बहुत उतार-चढ़ाव होता है, जबकि कोर मुद्रास्फीति धीरे-धीरे ऊपर या नीचे जाती है।
- ऐसे में, यदि कोर मुद्रास्फीति 6% पर है, तो यह आरबीआई के लिए अधिक चिंताजनक होना चाहिए था।

5. मौद्रिक नीति का पिछड़ापन

- अक्सर यह सोचा जाता है कि जैसे ही आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ाता या घटाता है, अर्थव्यवस्था तुरंत प्रतिक्रिया देगी।
- लेकिन ऐसा नहीं होता है। हालांकि इस तरह के "मौद्रिक नीति प्रसारण" में समय के साथ सुधार हुआ है, फिर भी इसे पूर्ण प्रभाव में आने में अभी भी समय लगता है।
- दूसरे शब्दों में, यदि आरबीआई मई में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहता है, तो उसे शायद फरवरी में या कम से कम अप्रैल में कार्रवाई करनी चाहिए थी।
- दरें बढ़ाने से मुद्रास्फीति दर में तुरंत कमी नहीं आएगी ।

गतिशीलता परिवर्तन

भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है , जो अपने शहरों को विश्व स्तरीय स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए बुनियादी ढांचे और परिवहन में भारी निवेश कर रहा है।

1. नई गतिशीलता समाधान के लिए नवाचार

- बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के साथ परिवर्तन करते हुए, उद्योग इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), कनेक्टेड कारों, सेंसर और मोबिलिटी-ए-ए-सर्विस जैसे नए बिजनेस मॉडल के भविष्य की ओर दौड़ रहा है।
- गैर-सेवा व्यवसाय वाहन निर्माण और डिजाइन को बदल रहे हैं।
- नए मोबिलिटी समाधान ऑटोमोटिव उद्योग में नवाचार के अग्रदूत हैं।

2. ऑटोमोबाइल उद्योग परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक

- ऑटो उद्योग में नवीनतम रुझान प्रौद्योगिकी द्वारा निर्देशित हैं।
- सॉफ्टवेयर क्षेत्र में बढ़ते सहयोग और उभरते स्टार्टअप के साथ पारंपरिक विनिर्माण से अत्याधुनिक डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है।
- पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) ऑटो उद्योग को तकनीकी रूप से परिष्कृत उद्योग में बदलने की पहल में तेजी से वृद्धि हुई है।

3. उपभोक्ता संबंधी चुनौतियां:

- उपभोक्ता चुनौतियों का समाधान करने के लिए एकीकृत गतिशीलता समाधान उभर रहे हैं।
- सुविधा आज की हाइपर-कनेक्टेड दुनिया में एक महत्वपूर्ण कारक है, जहां उपयोग में आसान, स्वचालित और डिजीटल विकल्पों को प्राथमिकता दी जाती है।
- बाजार के रुझान का अनुमान लगाने और व्यापार मॉडल की उपभोक्ता व्यवहार्यता की खोज करने के लिए टेलीमैटिक्स की मदद से उपभोक्ता वरीयताओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।
- ये ट्रैकिंग उपकरण एक व्यवसाय को अधिक चुस्त बनने में मदद करते हैं और नए अवसरों की पहचान और पैमाने भी करते हैं।

- **अर्धचालकों की कमी :**
  - o ऑटोमोबाइल क्षेत्र भी विश्व स्तर पर सेमीकंडक्टर की कमी से गुजर रहा है।
  - o ऑटोमोबाइल में अब अधिक इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं, जो स्मार्ट कनेक्टिविटी सुविधाओं द्वारा संचालित हैं और कड़े उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए रिइंजीनियरड हैं।

4. सतत गतिशीलता की ओर बदलाव

- वैश्विक CO_2 नियमों ने उद्योग को नवीनतम नवाचारों को अपनाने में चुस्त होने के लिए प्रेरित किया है।
- जलवायु परिवर्तन को धीमा करने के लिए सतत विकास की ओर एक बदलाव किया जा रहा है।
- मेट्रो शहरों में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं:

a) इस केंद्रीय बजट में शहरी जीवाश्म-ईंधन क्षेत्र बनाने, एक बैटरी-स्वैपिंग नीति और सेवा के रूप में ऊर्जा की मान्यता पर जोर दिया गया है।

b) सरकार ने FAME -2 योजना को और तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया है तथा 2 और 3 व्हीलर बैटरी के लिए प्रोत्साहन बढ़ा दिया है।

c) एसीसी बैटरी भंडारण इकाइयों और ऑटो उत्पादों के साथ-साथ ऑटो घटकों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं मौजूद हैं। इस योजना के तहत अब 20 ऑटोमोबाइल और 75 ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं को मंजूरी मिल गई है।

d) एक और ऐतिहासिक घोषणा हरित हाइड्रोजन पर भारत की नीति थी, जो भारत को इसके उत्पादन में अग्रणी बनाने का प्रयास करने को प्रेरित है।

5. प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य

- **उपयुक्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर :**
  - o ई-मोबिलिटी के विस्तार और एकीकरण के लिए कई क्षेत्रों पर काम करने की आवश्यकता है।
  - o रेंज की चिंता उपभोक्ताओं के लिए विवाद का विषय है, ये ईवी के डिसचार्ज होने की स्थिति में फंसे होने से डरते हैं।
- **बैटरियों की लागत :**
  - o बैटरियों की लागत, जो ईवी की कुल लागत को बढ़ाती है, पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
  - o पीएलआई योजनाएं जो बैटरी उत्पादन, नई बैटरी रसायन और स्वैपेबल बैटरी मॉडल के स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करती हैं, से एक बड़ा पुश मिलने की उम्मीद है।
- **निवेश में वृद्धि :**
  - o कंपोनेंट कंपनियों द्वारा मैन्युफैक्चरिंग में निवेश को कंपोनेंट्स के लिए डिमांड एग्रीगेशन के जरिए बढ़ाया जा सकता है।
  - o गैर-आवश्यक वस्तुएं जैसे मोटर और कनेक्टर आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
  - o प्रारंभिक चरण से उत्पादों को विकसित करने के लिए मूल उपकरण और घटक निर्माताओं को ईवी स्पेस में मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी।

MSMEs के डिजिटल होने की आवश्यकता

'डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन' देश में चर्चा का विषय है। इस तरह के परिवर्तन का विचार डराने वाला हो सकता है और अक्सर यही एक कारण है कि डिजि. टल समाधानों का मूल्यांकन करते समय एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) दुविधा में होते हैं।

1. डिजिटलीकरण के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना

- महामारी ने डिजिटल रूप से सक्षम होने की आवश्यकता को सामने ला दिया है।
- हालांकि यह विकास पारंपरिक छोटे व्यवसायों के लिए खर्चीला हो सकता है, वे इस तथ्य से सांत्वना ले सकते हैं कि सभी व्यवसायों के मूल में ग्राहक विश्वास बनाने की आवश्यकता है।
- पारंपरिक व्यवसाय जो कई वर्षों से चल रहे हैं, इस मामले में नए व्यवसायों पर एक निश्चित बढ़त की स्थिति में है।
- ऐसे एसएमबी मुख्य समस्याओं की पहचान करके और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकृत करके अपना डिजिटल परिवर्तन शुरू कर सकते हैं।
- यह प्रक्रिया इस बारे में भी जानकारी देगी कि कंपनियां अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा को कैसे चरणबद्ध कर सकती हैं।
- महामारी ने आगे के बदलाव के अनुकूल होने में बहुत बड़ा बदलाव लाया है:
  - o स्वचालित कार्यप्रवाह हो।
  - o ई–कॉमर्स में स्थानांतरण।
  - o **D2C** ब्रांडों में कनवर्ट करना।
  - o भुगतान गेटवे का उपयोग करना।
  - o दूरस्थ संचार उपकरण आदि।
- इन्वेंट्री प्रबंधन सुधार शुरू करने के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी।

2. हाइब्रिड मॉडल समय की मांग

(वास्तविकता यह है कि पारंपरिक व्यवसायों में भौतिक या वर्चुअल को अपने मुख्य आधार के रूप में चुनने या हाइब्रिड मॉडल का विकल्प चुनने का लचीलापन होता है।

(खुदरा बाजार में ऑनलाइन ईकॉमर्स स्टोर और प्ले. टफॉर्म भौतिक स्टोर स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं।

(भारत में भी, यह स्पष्ट है: लोकप्रिय ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर ने प्रमुख शहरों और कस्बों में भौतिक 'अनुभव' केंद्र स्थापित किए हैं।

(ग्राहक अभी भी कुछ उत्पादों या सेवाओं का अनुभव करना पसंद करते हैं, और व्यक्तिगत बैठकें बिक्री से पहले सबसे महत्वपूर्ण विश्वास कारक बनाती हैं।

3. कर्मचारियों को प्रशिक्षण

- पाठ्यक्रम के डिजिटल परिवर्तन के लिए कुछ प्रशिक्षण और पुनर्संरचना की आवश्यकता है।
- व्यवसाय के स्वामी, टीम को प्रशिक्षित करने और उपकरणों के उपयोग के प्रशिक्षण हेतु लीडर्स को नामित कर सकते हैं।
- सभी को बोर्ड पर लाना महत्वपूर्ण है।
- अधिकांश उद्यमी और छोटे व्यवसाय के मालिक ऐसे सामान्यवा. दियों को नियुक्त करते हैं जो मल्टी–टास्किंग होते हैं।
- कुछ विशेषज्ञों को काम पर रखने से दीर्घकालिक डिजिटल क्षमता विकसित करने में मदद मिलती है।
- व्यवसाय भी खुद को फिर से संगठित करते हैं और कामकाज के मामले में स्पष्टता लाने के लिए अपने कर्मचारियों को फिर से काम का आवंटन करते हैं।

- महामारी के दौरान आपूर्ति शृंखला में व्यवधान एक आम समस्या बन गई है, और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन ने कुछ व्यवसायों को दूसरों पर बढ़त हासिल करने में मदद की है।
- बी2सी क्षेत्र में, व्यवसायों को तेजी से ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने से लाभ हुआ है।
- कई व्यवसायों ने अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति को एजेंसियों पर छोड़ने के बजाय सीधे प्रबंधित करना शुरू कर दिया।
- सोशल मीडिया मार्केटिंग उनके ब्रांड संचार का एक अभिन्न अंग बन गया है।

4. डिजिटल प्रशिक्षण

(इसके लिए त्रिस्तरीय रणनीति इस प्रकार है:

- o चूंकि उम्र, निवास स्थान और प्रतिभागियों की आय में अर्जित लाभों में भिन्नताएं मौजूद हैं, सामुदायिक भागीदारी के साथ प्रशिक्षण के लिए एक अधिक विकेन्द्रीकृत कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है।
- o छोटे व्यवसायों के लिए बड़े पैमाने पर आईसीटी हस्तक्षेप और प्रशिक्षण में संलग्न होने से पहले यह पता लग. ाने की आवश्यकता है कि ग्रामीण उद्यमियों को किन विशिष्ट बाधाओं का अनुभव होता है।
- o इस तरह के हस्तक्षेपों को डिजाइन करने में संस्थानों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मध्यम अवधि की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा क्योंकि एक बार के प्रशिक्षण से वांछित परिणाम नहीं मिल सकते हैं।

बैटरी स्वैपिंग नीति

सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने हाल ही में एक मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की जिसके तहत पहले चरण के तहत बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरों को प्राथमिकता दी जाएगी।

1. बैटरी स्वैपिंग के बारे में

- बैटरी स्वैपिंग एक ऐसा तंत्र है जिसमें चार्ज की गई बैटरी के लिए डिस्चार्ज की गई बैटरी का आदान-प्रदान करना शामिल है।
- यह इन बैटरियों को चार्ज करने और उपयोग करने के अलग अलग तंत्र विकसित करने की सुविधा प्रदान करता है, और नगण्य डाउनटाइम के साथ वाहन को परिचालन मोड में रखता है।

2. प्रमुख प्रस्ताव

- लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण पर कर दरों के बीच अंतर कम होना चाहिए। वर्तमान में, बैटरी पर 18% GST लगता है, जबकि EV आपूर्ति उपकरण पर 5% जीएसटी लगता है।
- राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सार्वजनिक बैटरी चार्जिंग स्टेशन रियायती दरों पर बिजली दरों के लिए पात्र हैं।
- बिना बैटरियों या स्वैपेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाना।
- स्वैपेबल बैटरियों और बैटरी चार्जिंग स्टेशनों को एक विशिष्ट पहचान संख्या निर्दिष्ट करें।
- स्वैपेबल बैटरी वाले वाहन बिना बैटरी के बेचे जाएंगे, जिससे संभावित ईवी मालिकों को कम खरीद लागत का लाभ मिलेगा।
- खुदरा ईंधन स्टेशनों, सार्वजनिक पार्किंग क्षेत्रों, मॉल आदि जैसे स्थानों पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करें।

3. बैटरी-एज-ए-सर्विस बिजनेस मॉडल

- सेवा के रूप में बैटरी व्यवसाय मॉडल वह है जिसमें कंपनियां समर्पित बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करती हैं।
- ये स्टेशन बदली जा सकने वाली बैटरियों का स्टॉक रखते हैं जिन्हें चार्ज करके स्टेशनों में रखा जाता है।
- जिन ग्राहकों के पास संगत ईवी हैं, वे सब्सक्रिप्शन या पे-एज-यू-गो मॉडल के लिए अपनी डिस्चार्ज की गई बैटरियों की अदला-बदली कर सकते हैं और इसे इन स्टेशनों पर चार्ज की गई बैटरी से बदल सकते हैं।

4. ईवी सुरक्षा के बारे में

- **कठोर परीक्षण प्रोटोकॉल**
  - o विद्युत इंटरफेस पर किसी भी अवांछित तापमान वृद्धि से बचने के लिए, विद्युत इंटरफेस पर उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एक कठोर परीक्षण प्रोटोकॉल अपनाया जाएगा।
- **बैटरी प्रबंधन प्रणाली**
  - o बैटरी प्रबंधन प्रणाली, जो एक सॉफ्टवेयर है जो बैटरी कार्यों को नियंत्रित करता है, को स्व-प्रमाणित और परीक्षण के लिए खुला होना चाहिए ताकि विभिन्न प्रणालियों के साथ इसकी संगतता और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता की जांच की जा सके।
  - o हाल ही में बिजली के दोपहिया वाहनों में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्व रखता है।
- **परीक्षण और प्रमाणित बैटरी**
  - o बैटरियों को ट्रैक्शन बैटरी पैक की सुरक्षा के लिए AIS 156 (2020) और AIS 038 Rev 2 (2020) मानकों के अनुसार परीक्षण और प्रमाणित किया जाएगा, साथ ही अतिरिक्त परीक्षण जो स्वैपेबल बैटरियों के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं जो मल्टीपल कपलिंग/डिकपलिंग के अधीन हैं।
- **एडवांस फीचर्स से लैस**

इसके अतिरिक्त, परिसंपत्तियों की बेहतर सुरक्षा के लिए, स्वैपेबल बैटरियों को IoT& आधारित बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम, रिमोट मॉनिटरिंग और इमोबिलाइजेशन क्षमताओं जैसी उन्नत सुविधाओं से लैस करना होगा

5. भावी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों की चिंताएं

- **ईवी की उच्च लागत:**
  - o हालांकि इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर के लिए स्वामित्व की कुल लागत की तुलना आंतरिक दहन इंजन **(ICE)** से की जा रही है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिग्रहण मूल्य अभी भी 30-50% अधिक है, जो कि **EV** स्केल अप में एक महत्वपूर्ण बाधा है।
- **उच्च बैटरी प्रतिस्थापन लागत:**
  - o उच्च श्रेणी के E2W के लिए बैटरी बदलने की लागत INR 45000 तक होने की उम्मीद है। इस मूल्य-प्रतिस्पर्धी 2W बाजार में बैटरी को बदलना एक महंगा विकल्प है।
- **बैटरियों का लंबा चार्जिंग समय:**
  - o राइडर्स ने अक्सर ICE वाहनों के लिए कम ईंधन रिफिलिंग समय के बजाय बैटरी के लंबे चार्जिंग समय को EV अपनाने में बाधाओं में से एक के रूप में उद्धृत किया है।

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न

Q1. वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा (GEF) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह देशों, सिविल सोसायटी संगठनों एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी है।
2. GEF जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन तथा ओजोन परत के लिए अनुदान करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

Q2. BSE-ग्रीनेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

(a) यह इंडेक्स BSE द्वारा प्प्ड अहमदाबाद के साथ भागीदारी द्वारा विकसित किया गया है।
(b) BSE ग्रीनेक्स कार्बन उत्सर्जन के आधार पर कम्पनियों के प्रदर्शन का मापन करेगा।
(c) नया इन्डेक्स न्यूनतम कार्बन फुट प्रिन्ट के आधार पर 20 स्टॉक्स से मिलकर बनेगा।
(d) उपर्युक्त सभी

Q3. 'बोरियाल वन' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसे हिमवन के नाम से भी जाना जाता है।
2. इनमें शंकुधारी वनों की विशेषताएं पाई जाती हैं।
3. यह विश्व का सबसे बड़ा पार्थिव बायोम है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1, 2 और 3
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 1 और 3

Q4. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

नमभूमियां		नदी क्षेत्र
1. रोपड़ नमभूमि	:	व्यास नदी संगम क्षेत्र
2. दीपोर बील नमभूमि	:	लोहित नदी संगम क्षेत्र
3. कांजली नमभूमि	:	सतलज नदी संगम क्षेत्र

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं ?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) 1, 2 और 3
(d) इनमें से कोई नहीं

Q5. निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों में सर्वाधिक बाघ हैं?

(a) मध्य प्रदेश और कर्नाटक
(b) उत्तराखण्ड और मध्य प्रदेश
(c) कर्नाटक और सिक्किम
(d) उत्तराखण्ड और सिक्किम

Q6. ऐसे जीव, जो तापमान की केवल निम्न परास को ही सहन कर सकते हैं, कहलाते हैं -

(a) यूकेरियोटिक जीव
(b) स्टेनोथर्मल
(c) यूरीथर्मल
(d) पाइरोथर्मल

Q7. पारितंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों में ऊर्जा का स्थानांतरण कहलाता है :

(a) बायोएनर्जेटिक्स
(b) बायोसिस्टम
(c) जीओबायोकोएनोसिस
(d) होलोकोएनोटिक

Q8. ऐसी प्रजाति, जो पारितंत्र में नगण्य संख्या में उपलब्ध होती हैं और अन्य दूसरी कई प्रजातियों के अस्तित्व निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, कहलाती हैं -

(a) की-स्टोन प्रजातियां
(b) पवित्र प्रजातियां
(c) स्थानिक प्रजातियां
(d) विलुप्त प्रजातियां

Q9. किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों के ह्रास के प्रमुख कारणों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए -

1. आवास क्षति एवं विखंडन
2. अतिदोहन
3. विदेशज प्रजाति
4. सह-विलुप्तता

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) 1, 2, 3 और 4
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 3 और 4
(d) केवल 1, 2 और 3

Q10. प्रकाश संश्लेषण के दौरान जैविक पदार्थों के उत्पादन की दर

कहलाती है ?

(a) शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता
(b) सकल प्राथमिक उत्पादकता
(c) द्वितीयक उत्पादकता
(d) (a) और (b) दोनों

Q11. निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

1. नए खुले चट्टान और बालू
2. नए खुले हिमनद
3. लावा प्रवाह
4. एक स्थिर पर्णपाती वन समुदाय

उपर्युक्त उदाहरणों में से कौन-से प्राथमिक अनुक्रमण/ उत्तराधिकार से संबंधित हैं ?

(a) 1, 2, 3 और 4
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 3
(d) केवल 3 और 4

Q12. ऐसे पौधे, जो अधिक लवणीय जल में या लवणीय जल के सम्पर्क से अपना विकास करते हैं, कहलाते हैं:

(a) हैलोफाइट
(b) जीरोफाइट
(c) एपीफाइट
(d) हाइड्रोफाइट

Q13. मरुस्थलीय पौधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मरूस्थल के अधिकतर पौधों के पास उनकी पत्तियों की सतह पर मोटी उपचर्म/उपत्वचा एवं रंध्रों पर गहरे गड्ढे होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल का ह्रास न्यूनतम हो।
2. इनके पास विशेष प्रकाश संश्लेषण मार्ग होता है जो दिन के समय रंध्रों को बंद रखने में सहायक होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

(a) 1 और 2 दोनों
(b) केवल 1
(c) केवल 2
(d) न तो 1 और न ही 2

Q14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. आमतौर पर शीत जलवायु में स्तनपायी के शरीर के अंग और कान छोटे होते हैं, ताकि न्यूनतम ऊष्मा का ह्रास हो।
2. ध्रुवीय समुद्री जलीय स्तनपायी जैसे- सील में त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है जो इंसुलेटर (अवरोधक) का कार्य करती है और शरीर के तापमान की कमी को कम करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Q15. निम्नलिखित जैवमंडल रिजर्व में से कौन-सा मैन एण्ड बायोस्फेयर रिजर्व कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है?

(a) सिमलीपाल जैवमण्डल
(b) निकोबार द्वीप समूह
(c) मानस जैवमण्डल
(d) नोकरेक जैवमण्डल

Q16. निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए :

जैवमण्डल रिजर्व	राज्य
A. कोल्ड डेजर्ट	1. सिक्किम
B. खंगचेंडजंगा	2. हिमाचल प्रदेश
C. डिब्रू-सिखोवा	3. अरूणाचल प्रदेश
D. दिहांग-दिबांग	4. असम

कूट :

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	2	1	3	4
(c)	2	1	4	3
(d)	3	2	1	4

Q17. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. रामदेव मिश्रा को भारत में 'पारिस्थितिकी का पिता' कहा जाता है।
2. भारत सरकार द्वारा पर्यावरण नियोजन एवं समन्वयन के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन वर्ष 1980 में किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Q18. निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए :

बाघ रिजर्व	राज्य
A. बांदीपुर	1. छत्तीसगढ़
B. मेलघाट	2. कर्नाटक
C. पलामू	3. महाराष्ट्र

D. इन्द्रावती 4. झारखण्ड

कूट :

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	1	3	4	2
(c)	2	4	3	1
(d)	2	3	4	1

Q19. इथेनॉल प्राप्ति के स्रोतों के बारे में निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए :

1. मक्का
2. गेहूँ
3. आलू अपशिष्ट
4. पनीर छाछ

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1
(d) 1, 2, 3 और 4

Q20. निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए :

जनजातियां		व्यवसाय
A. टोडा	1.	कृषक
B. बडागा	2.	दुग्ध उत्पादक
C. कोटा	3.	हस्तशिल्प कलाकार
D. इरूला	4.	खाद्य संग्राहक
E. कुरूम्बास	5.	जादू-टोना करने वाले

कूट :

	A	B	C	D	E
(a)	2	1	3	4	5
(b)	1	2	3	4	5
(c)	2	1	4	3	5
(d)	1	2	4	3	5

Q21. केरल, कर्नाटक एवं अरूणाचल प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं ?

(a) उष्णकटिबंधीय पर्णपाती
(b) उष्णकटिबंधीय सदाबहार
(c) पर्वतीय वन
(d) उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन

Q22. निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए :

खण्ड I	खण्ड II
A. पौधे	1. उपभोक्ता
B. जीव-जंतु	2. स्वपोषक
C. मानव	3. मांसाहारी
D. शेर	4. सर्वाहारी

कूट :

	A	B	C	D
(a)	2	1	4	3
(b)	1	2	3	4
(c)	2	1	3	4
(d)	2	3	4	1

Q23. दक्षिण एशिया क्षेत्र में निम्नलिखित देशों में से किस देश ने मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है?

(a) भारत
(b) श्रीलंका
(c) पाकिस्तान
(d) बांग्लादेश

Q24. 'इथेनॉल' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसका प्रयोग भविष्य में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है।
2. यह एल्कोहल का एक प्रकार है जिसे शर्करा के किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है।
3. आलू और अनाज से प्राप्त स्टार्च का प्रयोग किण्वन में किया जाता है।
4. इथेनॉल का प्रयोग, पेट्रोल में मिश्रित कर मोटर वाहनों को चलाने में किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं ?

(a) 1, 2, 3 और 4
(b) 1, 2 और 3
(c) 2, 3 और 4
(d) 3 और 4

Q25. जैव खनन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह माइक्रोबियल लीचिंग का एक प्रकार है।
2. यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें चट्टानों के अयस्क से सूक्ष्म जीवों द्वारा धातुऐं प्राप्त की जाती हैं।
3. निम्न स्तरीय अयस्कों में निकिल, सीसा, जिंक पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिन्हें जैव खनन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

(a) केवल 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

Q26. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. जैव-उपचार का तात्पर्य सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से अपशिष्ट पदार्थों के निम्नीकरण की एक प्रक्रिया से है।
2. यह प्रक्रिया मृदा में नए बैक्टीरिया को जोड़कर अथवा अपशिष्ट में बैक्टीरिया की गतिविधि को उत्प्रेरित करने के लिए पोषकों को समाहित कर सम्पन्न की जा सकती है।
3. नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैव-उपचार का एक प्रकार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

(a) केवल 3
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q27. 'एंजाइम' के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?

(a) एंजाइम हार्मोन्स होते हैं जिन्हें जैव-रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा उत्पादित किया जाता है।
(b) ये सूक्ष्म जीवों, जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों द्वारा तैयार किये जाते हैं।
(c) एंजाइमों के औद्योगिक उत्पादन द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित एंजाइमों का प्रयोग वाणिज्यिक क्रियाओं में किया जाता है।
(d) इनमें से कोई नहीं।

Q28. जैव-आवर्द्धन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही क्रम है?

(a) शैवाल मछली शेलफिश मानव
(b) शैवाल शेलफिश मछली मानव
(c) शेलफिश शैवाल मछली मानव
(d) शेलफिश मछली शैवाल मानव

Q29. निम्नलिखित में से कौन-सा सतत् विकास संकल्पना से संबंधित है?

(a) ब्रंटलैंड आयोग
(b) फुलब्राइट आयोग
(c) हॉल्ड्रेन आयोग
(d) इनमें से कोई नहीं

Q30. स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 केन्द्रित था :

(a) वन्यजीवन संरक्षण पर
(b) जैव विविधता संरक्षण पर
(c) वन संरक्षण पर
(d) मानव पर्यावरण पर

उत्तर

1.	(c)	16.	(c)
2.	(d)	17.	(a)
3.	(a)	18.	(d)
4.	(d)	19.	(d)
5.	(a)	20.	(a)
6.	(b)	21.	(b)
7.	(a)	22.	(a)
8.	(a)	23.	(b)
9.	(a)	24.	(a)
10.	(b)	25.	(d)
11.	(c)	26.	(b)
12.	(a)	27.	(a)
13.	(a)	28.	(b)
14.	(c)	29.	(a)
15.	(c)	30.	(d)

समसामायिक आधारित बहुविकल्पी प्रश्न

Q1. नेत्रा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. यह इसरो की अंतरिक्ष मलबा ट्रैकिंग क्षमता को बढ़ाने की योजना पर आधारित है।
2. इस राडार की विशेषता यह है कि यह 5 सेमी से अधिक आकार की वस्तुओं का पता लगा सकने में सक्षम है।
3. इसरो 1000 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे दो राडार तैनात करेगा।

कूटों का प्रयोग करके सही कथन/कथनों का चुनाव करें।

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) सभी सत्य हैं

उत्तर : b

Q2. देश में फल उत्पादन के संबंध में शीर्ष राज्यों का सही क्रम क्या है ?

(a) आंध्र प्रदेशझ महाराष्ट्रझ उत्तर प्रदेशझ कर्नाटकझ गुजरात
(b) आंध्र प्रदेशझ उत्तर प्रदेशझ महाराष्ट्रझ कर्नाटकझ गुजरात
(c) आंध्र प्रदेशझ कर्नाटकझ महाराष्ट्रझ उत्तर प्रदेशझ गुजरात
(d) आंध्र प्रदेशझ महाराष्ट्रझझ गुजरातझ उत्तर प्रदेशझ कर्नाटक

उत्तर : a

Q3. द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास श्वरुणश के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. हाल ही में इस अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया
2. यह भारत तथा ब्रिटेन के मध्य आयोजित होने वाला नौसेना अभ्यास है।
3. यह इस तरह के अभ्यास का 22वां संस्करण है।

कूटों का प्रयोग करके सही कथन/कथनों का चुनाव करें।

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) सभी असत्य हैं

उत्तर : d

Q4. देश में सब्जी उत्पादन के संबंध में शीर्ष राज्यों का सही क्रम क्या है ?

(a) उत्तर प्रदेश झ मध्य प्रदेशझ पश्चिम बंगाल > बिहार > महाराष्ट्र
(b) उत्तर प्रदेश झ पश्चिम बंगाल > मध्य प्रदेश झ बिहार > महाराष्ट्र
(c) उत्तर प्रदेश झ मध्य प्रदेशझ महाराष्ट्र > बिहार > पश्चिम बंगाल
(d) महाराष्ट्र झउत्तर प्रदेश > मध्य प्रदेशझ पश्चिम बंगाल > बिहार

उत्तर : b

Q5. भारत तथा चीन के बीच द्वीपक्षीय व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पिछले वित्त वर्ष में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 155.62 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
2. भारत मुख्य रूप से चीन को लौह अयस्क, हीरे, एल्यूमीनियम और परिष्कृत तांबे के कैथोड का निर्यात करता है।

कूटों का प्रयोग करके सही कथन/कथनों का चुनाव करें।

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1
(c) केवल 2
(d) दोनों सत्य हैं

उत्तर : c

Q6. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?

(a) यह असम में ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ग्रस्त मैदानों में स्थित है।
(b) इसे 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
(c) इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था।
(d) यहां देश में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी है।

उत्तर : b

Q7. निम्न में कौन हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) का सदस्य नहीं है?

(a) दक्षिण अफ्रीका
(b) तंजानिया
(c) ऑस्ट्रेलिया
(d) मंगोलिया

उत्तर : d

Q8. हाल ही में किन दो स्थानों को भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों के रूप में मान्यता दी गयी है?

(a) शिवालिक जीवाश्म पार्क और स्ट्रोमेटोलाइट युक्त डोलोमाइट/बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर (सिक्किम)।
(b) शिवालिक जीवाश्म पार्क और ज्वालामुखीय बेडेड बैराइट्स,

मंगमपेटा, कडप्पा जिला।

(c) स्ट्रोमेटोलाइट युक्त डोलोमाइट/बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर (सिक्किम) और ज्वालामुखीय बेडेड बैराइट्स, मंगमपेटा, कडप्पा जिला।

(d) वेल्डेड टफ, जोधपुर जिला और प्राकृतिक भूवैज्ञानिक आर्क, तिरुमाला हिल्स, चित्तूर जिला।

उत्तर : a

Q9. अदालतों के आदेशों के तेज और सुरक्षित प्रसारण के लिए किस प्रणाली कि शुरुवात की गयी है?

(a) द्रुतगति

(b) तेज

(c) फास्टर

(d) शक्ति

उत्तर : c

Q10. हाल ही में किस राज्य ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 100% नामांकन के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुवात की है?

(a) मध्य प्रदेश

(b) उत्तर प्रदेश

(c) दिल्ली

(d) पंजाब

उत्तर : b

Q11. निम्न में से किस/किन भारतियों को 64वां ग्रैमी पुरूस्कार मिला है?

(a) रिकी केज

(b) फाल्गुनी शाह

(c) दोनों को

(d) इनमें से किसी ओ भी नहीं

उत्तर : c

Q12. वर्तमान में भारत में कुल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं?

(a) 32

(b) 34

(c) 36

(d) 40

उत्तर : b

Q13. हाल ही में संपन्न आईएमईएक्स समुद्री अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?

1. 25 सदस्यी आईओएनएस में से 15 सदस्यों ने इसमें भाग लिया।
2. यह अभ्यास सदस्य देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से सामूहिक रूप से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है।
3. आईएमईएक्स-22 का बंदरगाह चरण गोवा के मोरमुगाओ बंदरगाह पर आयोजित किया गया।

कूटों का प्रयोग करके सही कथन/कथनों का चुनाव करें।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1

(c) केवल 2

(d) तीनों सत्य हैं

उत्तर : d

Q14. एक सींग वाले गैंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

एक सींग वाले गैंडे को आईयूसीएन लाल सूची में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में नई जनगणना के अनुसार एक सींग वाले गैंडों की आबादी 4,613 तक पहुंच गई है।

कूटों का प्रयोग करके सही कथन/कथनों का चुनाव करें।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1

(c) केवल 2

(d) तीनों सत्य हैं

उत्तर : b

Q15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. कार्बन पृथक्करण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर और संग्रहीत करने की प्रक्रिया है।
2. कार्बन कैप्चर की विधियों के अंतर्गत जैविक, भूवैज्ञानिक और तकनीकी विधियां शामिल हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) दोनों 1 और 2

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर : c

Paper IV केस स्टडी

महाराष्ट्र में प्याज की अच्छी फसल होने से इसका बाजार मूल्य घटकर 500 रूपये प्रति क्विंटल हो गया है। सरकार ने किसानों के हित में प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रूपये प्रति क्विंटल घोषित करते हुए, सभी प्याज खरीद केन्द्रों को किसानों से प्याज खरीदने के आदेश जारी कर दिए है।

बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य में, भारी अंतर होने के कारण बहुत से दलालों ने, खरीद केन्द्रों के कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर ली। ये दलाल, व्यापारियों के गोदामों में स्थित पिछले वर्ष के प्याज को, खरीद केन्द्रों पर विक्रय करने में उनकी सहायता कर रहे हैं।

नासिक के किसानों को अपना प्याज विक्रय करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे किराये की ट्रालियों में प्याज रखकर, कई दिनों तक लाइन में खड़े रहते हैं, जिससे इनकी लागत बढ़ जाती है। जुलाई का महीना होने से, जलवायु ऊष्ण और आद्र है। बारिश में भीगने और फिर धूप लगने से प्याज अक्सर सड़ जाते है।

हताश होकर किसानों ने राष्ट्रीय महामार्ग पर अपने ट्रैक्टर-ट्राली खड़ा करके इसे अवरूद्ध कर दिया। इससे वाहनों का आवागमन और वस्तुओं का परिवहन, दोनों रूक गया है। इंदौर के नागरिकों को भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर पड़ रहा है।

इस प्रकरण की जानकारी मिलते ही सरकार ने इंदौर के जिलाधिकारी का तबादला कर दिया और आपको वहां का जिलाधिकारी नियुक्त करते हुए समस्या के शीघ्र समाधान के लिए निर्देश दिये।

(a) इस प्रकरण से सम्बन्धित विभिन्न नैतिक मुद्दों की विवेचना कीजिए।

(b) अब आप क्या कार्यवाही करेंगे।

दिये गए मामले में मुझे तत्काल इंदौर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के प्याज की खरीद सुनिश्चित करके सामान्य स्थिति बहाल करना है। इस प्रकरण में ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, निष्पक्षता, करुणा और न्याय जैसे मूल्य निहित हैं।

नैतिक मुद्दे

दिए गए मामले में किसानों की दुर्दशा दिखाई गई है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है लेकिन दलाल, खरीद केन्द्र के कर्मचारी और व्यापारी सांठगांठ करके किसानों को ठग रहे हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाये। हरित क्रान्ति, तकनीक के प्रयोग एवं किसानों के कठिन परिश्रम से प्रति हेक्टेयर अनाज के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है। लेकिन किसान अभी भी गरीब हैं। फसलों की अच्छी पैदावार एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उनकी सहायता नहीं कर पाता है।

दूसरी तरफ रासायनिक उर्वरकों, खर-पतवार नाशक, कीटनाशक एवं मशीनों के प्रयोग से कृषि की लागत बढ़ गई है।

खुश और संतुष्ट किसान अर्थव्यवस्था का आधार हैं, लेकिन इन्हें अपनी फसल की कीमत के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे विरोध प्रदर्शन, व्यापार एवं आम नागरिकों के जीवन को भी बाधित करते हैं। यदि इनकी समस्याओं का उचित समाधान नहीं किया गया तो आन्दोलन हिंसक हो सकता है।

किसी भी वर्ग की गरीबी, समाज के हर वर्ग की सम्पन्नता के लिए खतरा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है। हमें एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रणाली विकसित करके किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा।

कार्यवाही

मैं आवश्यक सुरक्षा बल के साथ तुरन्त खरीद केन्द्र पर छापा डालकर वहाँ उपस्थित सभी दलालों एवं व्यापारियों को गिरफ्तार कर लूँगा। हम उनके प्याज और वाहनों को जब्त कर लेंगे। मैं संबंधित दस्तावेज अपने कब्जे में ले लूँगा और जाँच पूरी होने तक के लिए इस ऋतु में खरीदे गए प्याज के भुगतान पर रोक लगा दूँगा। मैं प्याज खरीद के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करूँगा। जिसके अनुसार केवल किसानों से ही उनकी पहचान करने के उपरान्त प्याज खरीदा जाएगा। पिछले वर्ष के प्याज की खरीद प्रतिबंधित कर दूँगा और शीघ्र ही किसानों के प्याज की खरीद आरम्भ करा दूँगा। मैं खरीद केन्द्र के प्रबंधन को टोकन व्यवस्था आरम्भ करने एवं नए काउंटर खोलने के लिए सहमत कर लूँगा। इससे किसानों के धन एवं समय की बचत होगी।

नए दिशा-निर्देश केवल बैंक के जरिए कीमत का भुगतान करेंगे किसानों और उनके वाहनों का ब्यौरा रखना अनिवार्य होगा।

तत्पश्चात मैं उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करूँगा और इसे किसानों के आरोपों एवं खरीद केन्द्रों के कर्मचारियों की भूमिका की जांच करके पांच दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहूँगा।

तत्पश्चात् मैं किसानों से मिलूँगा और खरीद केन्द्र पर बारिश से सड़ गई प्याज की फसल के लिए हर्जाने की घोषणा करूँगा। मैं उन्हें अपने कार्यालय का फोन नम्बर देकर भविष्य में भी प्रशासन के सहयोग के प्रति आश्वस्त करूँगा। इससे प्रशासन में उनका विश्वास बहाल हो जाएगा। अत: मैं उन्हें आसानी से धरना समाप्त करने और खरीद केन्द्र जाकर प्याज विक्रय करने के लिए सहमत कर लूँगा। उपजिलाधिकारी की रिपोर्ट मिलते ही मैं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करूँगा। इससे किसानों को न्याय मिल जायेगा और भविष्य के लिए एक सबक हो जाएगा।

व्यक्ति विशेष : रवींद्रनाथ नाथ टैगोर

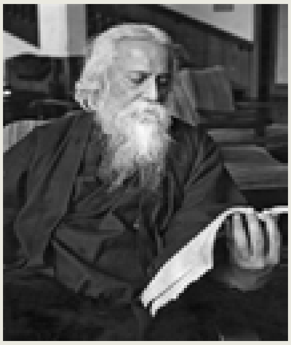

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर विख्यात बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। इन्होंने ने न केवल भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ रूप से पश्चिमी देशों का परिचय बल्कि पश्चिमी देशों की संस्कृति से भारत का परिचय कराने में महती भूमिका निभाई।

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। वह दुनिया के एकमात्र अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी-भारत का राष्ट्र-गान 'जन गण मन' और बाँग्लादेश का राष्ट्रीय गान 'आमार सोनार बाँग्ला'। इन्होंने ने बांग्ला साहित्य और संगीत को एक नई दिशा देते हुए बंगाली साहित्य को क्लासिकल संस्कृत के प्रभाव से मुक्त कराया।

रवींद्रनाथटैगोर का जन्म 7 मई 1861 को वर्तमान कोल. काता के जोड़ासाँ के ठाकुरबाड़ी में हुआ था । इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के अग्रणी नेता थे। टैगोर परिवार का 'बंगाली पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। रवींद्रनाथटैगोर के बड़े भाई द्विजेन्द्रनाथ दार्शनिक और कवि थे वही उनके दूसरे भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सेवा में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। 1883 में रवींद्रनाथ टैगोर का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। सन 1901 में रवींद्रनाथ टैगोर शांतिनिकेतन गए और यहां पर एक आश्रम की स्थापना की।

1940 के पास कमजोर स्वास्थ्य के कारण रवींद्रनाथ टैगोर ने बाहर आना जाना छोड़ दिया, लेकिन जब भी वह स्वस्थ होते तो एक से एक उत्कृष्ट रचनाओं को नए जोश के साथ सृजन करते हैं। अंततोगत्वा इस महान आत्मा ने सदा के लिए 7 अगस्त 1941 इस धरती को अलविदा कह दिया।

एक कला प्रेमी के रूप में रवींद्रनाथटैगोर

रवींद्रनाथ टैगोर को शुरुआती उम्र में ही कविता लिखने की रुचि विकसित हो गयी थी। 1890 के दशक मे इनके कई कविताएं, कहानियां और उपन्यास प्रकाशित हुए और वे बंगाल में प्रसिद्ध हो गए। ग्रामीण अंचलों का भ्रमण करते हुए तात्कालिक ग्रामीण बंगाल के पृष्ठभूमि पर कई लघु कथाएं लिखीं।

1913 में रवींद्रनाथटैगोर को गीतांजलि और उनके अन्य कृतियों के आधार पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें 1915 में नाइटहुड उपाधि प्रदान की गई जिसे रवींद्रनाथटैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया।

रवींद्रनाथटैगोर ने कविताओं के साथ साथ उपन्यास, लेख, लघु कहा. नियां, यात्रा-वृत्तांत, ड्रामा और हजारों गीत भी लिखे। उनके द्वारा लिखे गए तकरीबन 2220 गीतों को रवीन्द्र गीत कहा जाता है जो बंगाली संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इनके कुछ महत्वपूर्ण गीतों में भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगीत शामिल है। इसके अलावा रवींद्रनाथटैगोर एक कुशल चित्रकार भी थे।

रवींद्रनाथटैगोर ने एक उत्कृष्ट कलाकार की भांति कला से जुड़े हर एक विधाओं से भारतीय संस्कृति को वैविध्य बनाया।

उत्कृष्ट मानवतावादी चिन्तक के रूप में

रवींद्रनाथ टैगोर पर भारतीय पुनर्जागरण एवं तात्कालिक यूरोपीय परिस्थितियों का व्यापक प्रभाव पड़ा। उन्होंने तात्कालिक समय में राष्ट्रवाद के ऊपर मानवतावाद को रखा। उन्होंने उपनिवेशवाद, नस्लवाद और उग्र राष्ट्रवाद को मानवता का दुश्मन माना। विश्व-बंधुत्व के प्रबल हिमायती थे और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रवाद की बजाय अन्तर्राष्ट्रवाद की पुनर्जोर वकालत की। रवींद्रनाथ टैगोर ने जिस राष्ट्रवाद की कल्पना की थी उसके दो बुनियादी तत्व थे - पहला मानवता और दूसरा स्वतंत्रता। उन्होंने राष्ट्रवाद की संकल्पना में मानवतावाद को अनुपस्थित मानते हुए, इसे जनता के स्वार्थ का एक उपकरण माना। उन्होंने मानवतावाद को हमेशा देशभक्ति एवं राष्ट्रवाद से ऊपर रखा इसीलिए उन्होंने सशस्त्र विद्रोह एवं क्रांति सहित किसी भी प्रकार के हिंसक आन्दोलन का खुलकर विरोध किया।

टैगोर राष्ट्र, राष्ट्र-राज्य और राष्ट्रवाद की अतिवादी संकल्पना के मुखर विरोधी थे, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से दूरी बनाए रखी लेकिन ऐसा नहीं था कि वह राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति वे उदासीन रहे। स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने 'आमार सोनार बांग्ला' गीत के द्वारा बंगाली एकता को आगे बढ़ाया तो वही स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में भाग लेते हुए रक्षाबंधन दिवस मनाने का सुझाव देते हुए इस आंदोलन में भाग लिया।

उन्होंने अपने भाषण और लेखों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के दमनकारी स्वरूप की सदैव भर्त्सना की। वैचारिक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन भी दिया।

संक्षेप में कहें तो राष्ट्रवाद की अतिवादी विचारधारा को छोड़ कर उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन का समर्थन किया।

मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख शब्दावलियां

फरसंग- 12,000 क्यूबिट (हाथ) की दूरी का माप।

फतहनामा- जीत का पत्र।

फातिहा- प्रार्थना, कुरान के पहले सात वाक्य, इसे विजय के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता था।

फतवा- शरीयत या धार्मिक कानूनों के अंतर्गत कानूनी फैसला।

फौजदार- सैनिक टुकड़ी का सेनानायक।

फवाजिल - प्रशासनिक खर्चे पूरे होने के बाद शेष बची राशि।

बंदेगान-ए-तुर्क चिहलगानी- चालिसा के नाम से प्रचलित तुर्क दास-अधिकारियों के 40 परिवार, जिन्होंने इल्तुतमिश और बलबन के शासन के बीच दिल्ली सल्तनत पर राज किया।

बंदियान-ए-ताजिक- गैर-तुर्क अधिकारी या दास जो मूलतः विदेशी थे।

बालाहार- खेतिहर किसानों का सबसे छोटा वर्ग या समूह।

बर- सार्वजनिक शाही दरबार।

बर्बेक- शाही दरबार का प्रभारी अधिकारी जिसे फारसी में अमीरे-हजिब कहा जाता था।

बारगह- अदालत।

बरीद- सूचनाएँ एकत्रित करने वाला गुप्तचर अधिकारी।

बारिद-ए-मुमालिक- राज्य की गुप्तचर सेवाओं का प्रभारी प्रमुख।

बसिम- राज्य के एजेंट या राजदूत।

बेक- एक उच्च पदाधिकारी।

बिस्वा- भूमि के माप की एक छोटी इकाई।

मंडी- अनाज मंडी।

मंसूर- शाही आदेश या आज्ञा।

मदद-ए-माश- धार्मिक व्यक्तियों को जीविका के रूप में दी जानेवाली पेंशन या भूमि अनुदान।

मदरसा- शिक्षा संस्थान।

मफरूज- करमुक्त भूमि।

महाजन- सूद पर धन देने वाले व्यक्ति।

महसूल- राज्य या प्रांत की सकल राजस्व आय।

मजालिस- मजलिस अर्थात् बैठक का बहुवचन।

मजलिस ए खास- सुल्तान और उसके उच्चाधिकारियों की बैठक।

मजलिस-ए-खिलावत- सुल्तान और उसके उच्चाधिकारियों की गोपनीय और गुप्त बैठक। यह सुल्तान की सर्वोच्च परामर्शदाता परिषद थी।

माल- धन, राजस्व, विशेष रूप से भू-राजस्व या लगान।

मालगुजारी-भू-राजस्व या कर का भुगतान।

महजर- महत्त्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के लिए आयोजित विशिष्ट व्यक्तियों और विद्वानों की बैठक।

मजमुआदार- लेखा विचरण रखने और उसकी जाँच करनेवाला अधिकारी।

मलिक- दिल्ली सल्तनत में इसका अर्थ सर्वोच्च अधिकारी था, जो खान से छोटा लेकिन अमीर से बड़ा होता था।

मलिका-ए-जहाँ- विश्व साम्राज्ञी या सुल्तान की मुख्य बेगम को दिया गया खिताब

मलिक नायब- सल्तनत का संरक्षक या सुल्तान की ओर से कार्य करने वाला अधिकारी।

मलिक कबीर- महान मलिक या वे मलिक जिनका सल्तनत में दूसरा सर्वोच्च स्थान था।

ध्येयIAS® most trusted since 2003

DHYEYA IAS® most trusted since 2003

ANNUAL SUBSCRIPTION OF PERFECT 7 CURRENT AFFAIRS MAGAZINE (FORTNIGHTLY)

About Perfect 7:

The role of Current Affairs in Civil Services has tremendously increased, in all the subjects of General Studies like Economy, Polity, Science and Technology, International Relations, Environment, etc.

Need: Knowledge of Current Affairs

Inadequate Solution: Monthly Magazines available in the Market.

Why Inadequate?

- All magazines are monthly: This means that you get to know about the event after more than one month and students are unable to match the pace with newspaper and other media.
- Not suitable for Civil Services: Events are not analyzed as these magazines also cater to the one day exams and hence they provide only factual information's.
- Too much to read in one go: A student is suddenly burdened to cover too many events in a short time which leads to stress.

Solution to all the above three issues is PERFECT 7 Magazine by Dhyeya IAS.

- Released Fortnightly: A student is abreast with the current events of the month, near real time.
- Detailed Analysis of every event: Civil Services demands a deeper understanding of events, concepts and its analyses and not just know the event and its date.
- Easy to study: Since the magazine is fortnightly, a student is saved from Information overload and can relate with the newspaper, TV and other media coverages with a profound understanding of the current happenings.

Features of PERFECT 7

Important conditions for an IAS/PCS centered magazine		PERFECT 7	OTHERS
• Fortnightly	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Civil Services Exam centered	Hindi	✓	*
	English	✓	*
• Micro-Analysis of current issues & not a mere compilation of facts	Hindi	✓	*
	English	✓	*
• Brain boosters for important issues	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Multiple choice questions & their solution based on brain boosters	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Case studies with model answers for Ethics	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Explanation of important theories through pictures & graphics.	Hindi	✓	×
	English	✓	×

(* some institutes)

Annual Subscription Fee along with Courier Charges:

Cost of the Magazine:	45 x 24 = Rs 1080
Price After 25% Discount	Rs 810
Courier Charges:	30 X 24 = Rs 720
Total Charges:	**Rs 1530**

Annual Subscription Fee for Student Collecting Magazine form Mukherjee Nagar Centre:

Cost of the Magazine:	45 x 24 = Rs 1080
Price After 25% Discount	Rs 810
Total Charges:	**Rs 810**

BANK ACCOUNT DETAILS

Account Holder:-	**Trueword Publication Private Limited**
Bank A/C -	**50200032675602**
IFSC:-	**HDFC0000609**

Terms and Condition:

1. Fee submitted one will not be refunded or adjusted in any condition.
2. Dhyeya IAS ensures no damage or delay during transit however some unavoidable circumstances are beyond our control. responsibility for the delay in delivery,
3. W put best efforts to make the Magazine reach to the subscribers by 10th & 25th of every month.
4. If due to COVID-19 Pandemic or any unforeseen natural disaster or by an act of God, Dhyeya IAS is not able to print the Magazine then the duration of subscription will be increased to compensate for the same.

Whatsapp: 9205184003

dhyeyaias.com

AN INTRODUCTION

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

Dhyeya IAS, two decades old institution, was founded by Mr.Vinay Singh and Mr. Q. H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential aspirants realize their dreams which is evident from the success stories of the previous years.

As the nation progresses, the young generations become more conscious and aware about their career options. There is plethora of jobs and one among them is civil services, the most prestigious service in the country, which needs no introduction. It attracts many young minds hailing from almost all spectra of academic disciplines. The popular belief that the examination for this service is only meant for the brilliant lots has become a taboo as it also attracts the hardworking, sincere and disciplined minds. The saying- "In the end passion and hard work can substitute natural talent" holds true. It gives immense power and opportunity for young folks to bring about the positive changes in the society which would bring harmony and development. It inculcates values, moral, ethos and feeling of national integrity.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move may invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. Classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals' capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything, you can only help him find it within himself.

We feel that despite brilliance and diligence, most of the students are lacking proper guidance and aptitude needed to clear Civil Services Examination. This is why, we at Dhyeya IAS amalgamated the traditional as well as modern approach of teaching by incorporating best educators of the industry ably supported by Academic Associates, Class Notes and printed Study Material, routine as well as surprise Tests. Due to its arduous efforts, Dhyeya IAS is able to carve a niche among all the civil services coaching institutes in India. Access to an institution is as important as the quality of Institution. Our faith in this philosophy made us grow. With 12 Face to Face Centers located in different parts in India, Distance Learning Program , Live Streaming Centers and Residential Academy, we have made truly pan India presence. Ever since the foundation the institute has produced a heavy pool of bureaucrats both at central and state level. Dhyeya IAS not only aims at imparting the content of civil services in best way but also nurturing the aspirants as leaders of tomorrow who have a responsibility of fulfilling the dreams of around 1.4 billion Indians. Dhyeya IAS has guided over 50,000 aspirants with more than 4500 selections in civil services. Our journey is a small contribution for the development of the society and nation by nurturing the potential civil services aspirants.

Considering the toughness of Civil Services Exam, where success rate is a meager 0.1 percent, Dhyeya IAS has continuously produced phenomenal results over the years. Year after Year Dhyeya IAS is being recognized for imparting guidance to civil services aspirants using benchmarked quality practices. On the basis of scalability, innovation, achievements, impact potential our efforts and contribution have been acknowledged and rewarded with Education Excellence Awards by ET NOW, Brands Academy, Times of India, etc. This has enhanced motivation, pride and self-esteem of entire Dhyeya family.

₹ 45

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744